सुरक्षा, शांति और समृद्धि

सजग भारत

1-15 अप्रैल, 2023 वर्ष-1 अंक-1

पुलिस सेवा

नागरिक केंद्रित बनाने का संकल्प

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

अनुक्रमणिका

केंद्रीय गृह सचिव का संदेश	3
संपादकीय	4
आतंकवाद को जड़ से मिटाने को प्रतिबद्ध सरकार	14
संवेदनशील पुलिसिंग ने कम की जनता और पुलिस के बीच दूरी	16
भरोसे का नाम है सीबीआई	23
साइबर अपराध पर कसना होगा शिकंजा	24
मैत्री का मंत्र और दिया जीवनदान	28
हर पल अपडेट होती पुलिस	30

विशेष रिपोर्ट

06 पुलिस सेवा

12 टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ता सरोकार

26 एक रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे

आजादी का अमृत महोत्सव

संदेश

श्री अजय कुमार भल्ला
केंद्रीय गृह सचिव

> **प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के गठन और उनकी दूरदृष्टि ने पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन की न केवल रूपरेखा बदली, बल्कि इसे नई दिल्ली से बाहर ले जाकर देश के अन्य शहरों तक पहुंचा दिया।**

लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। पूर्वोत्तर के राज्यों में जिस प्रकार से शांति का वातावरण स्थापित हुआ है, वह सरकार की नीतियों और सटीक कार्ययोजना का प्रतिफल है। केंद्र और राज्य के पुलिस बलों के साथ केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं।

पुलिस बलों को दिशा-निर्देशन के मामले में प्रत्येक वर्ष होने वाला पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण इवेंट होता है। केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के गठन और उनकी दूरदृष्टि ने इस सम्मेलन की न केवल रूपरेखा बदली, बल्कि इसे नई दिल्ली से बाहर ले जाकर देश के अन्य शहरों तक पहुंचा दिया। ऐसा करने के पीछे प्रमुख वजह यही रही कि राज्यों के पुलिस बलों के साथ इस सम्मेलन की नज़दीकी बढ़ी और पूरे देश के पुलिस उच्चाधिकारियों को उस राज्य की पुलिस फोर्स से जुड़े लोगों से संवाद करने का अवसर मिला।

वर्ष 2014 से लेकर अब तक के सभी सम्मेलनों में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से यही संदेश दिया जा रहा है कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इन सम्मेलनों में प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री वरिष्ठ अधिकारियों से समग्र जानकारी लेते हैं और संवाद करते हैं। इससे पुलिस फोर्स को अधिक सक्षम और लोगों के प्रति संवेदनशील बनाने में मदद मिलती है। चुनौती के समय संवाद हमेशा नए रास्तों का निर्माण करने में सहायक होता है।

पुलिस बल के लिए प्रौद्योगिकी और ह्यूमन इंटरफेस के महत्व को हर कोई जानता है। 5जी के समय में सभी को साइबर सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना होगा। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में सभी को तकनीकी रूप से दक्ष होना होगा। आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता के लिए अन्य देशों के अनुरोधों को पारस्परिकता के हिस्से के रूप में प्राथमिकता से लिया जाना चाहिए। गृह मंत्रालय ने एमएलएटी/एलआर अनुरोधों पर एक नया ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है, जिसका उपयोग भी हो रहा है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय देश के भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधताओं के बीच बेहतर समन्वय का काम करता है। हमारे देश की पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) हर नापाक इरादों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं।

हमें पूर्ण विश्वास है कि आजादी के अमृत काल में सब मिलकर पहले से भी बेहतर काम करेंगे। इस वर्ष देश के सभी नागरिकों की जिम्मेदारी पहले से अधिक है। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। हम सबका पुनीत कर्तव्य है कि देश की लोकतांत्रिक परंपरा के अनुरूप अपना पूर्ण सहयोग दें।

जय हिंद

संपादक
की कलम से

श्री बालाजी श्रीवास्तव
महानिदेशक, बीपीआरएंडडी

> पुलिस बल न केवल समाज और जनता के प्रति अधिक संवेदनशील हुआ है, बल्कि केंद्र और राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ने से आपराधिक मामलों के निपटारे और उन्हें होने से रोकने के प्रयासों में भी तेज़ी आई है।

कानून व्यवस्था की बदलती चुनौतियां और देश में आंतरिक सुरक्षा के उच्च स्तर को बनाये रखने के लिए पुलिस फोर्स पूरी तरह तैयार है। बीते कुछ वर्षों में पुलिस बल को आधुनिक बनाने के साथ-साथ उसे सामर्थ्यवान बनाने की दिशा में काफी काम हुआ है। पुलिस बल न केवल समाज और जनता के प्रति अधिक संवेदनशील हुआ है, बल्कि केंद्र और राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ने से आपराधिक मामलों के निपटारे और उन्हें होने से रोकने के प्रयासों में भी तेज़ी आई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर दशकों से नई दिल्ली में होने वाले पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन को अब देश के अन्य शहरों में आयोजित किया जाने लगा है जिससे पूरे देश की पुलिस फोर्स में आत्मीयता और समन्वय का भाव पैदा हुआ है। इस बदलाव ने प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप पुलिस बल को नागरिक केंद्रित बनाया है। समय और आवश्यकता के अनरूप हुए बदलावों ने पुलिस बल का चेहरा बदला है और जनता के अधिक करीब आया है।

स्वतंत्रता के इस अमृत काल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत के स्वर्णिम युग की ओर पूरे विश्व का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं। इससे प्रत्येक भारतीय आह्लादित है। उसी आह्लाद के पल को संजोने के प्रयास में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली 'सजग भारत' पाक्षिक पत्रिका लेकर आपके समक्ष है। पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलनों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी निरंतर समसामयिक मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट कराते रहे हैं। इस अंक में हमने उन्हीं बातों को समाहित करने का प्रयास किया है। साल 2014 से लेकर अब तक के सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने पुलिस बलों से संबंधित जिन अहम मुद्दों पर ज़ोर दिया, उन्हें लेकर यह अंक तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री जी का पुलिस बलों से सदैव आग्रह रहा कि उन सभी मुद्दों पर खास ध्यान देने की आवश्यकता है, जिनका लाभ अंततः देश की जनता को मिल सके।

हमारा अनुभव बताता है कि देश के सभी पुलिस बल जिस भावना, समर्पण और निष्ठा के साथ जनहित में काम कर रहे हैं, उसकी सही तस्वीर आम जन तक नहीं पहुंच पा रही है। इसकी वजह से पुलिस बलों के कार्यों एवं क्षमता को लेकर जो सामाजिक मान्यता मिलनी चाहिए, वह अब तक नहीं मिल पाई है। हम इस पत्रिका को सोशल मीडिया के जरिए भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। स्वयं प्रधानमंत्री जी भी समाज में सकारात्मकता का प्रसार करने के लिए सोशल मीडिया के मंचों का उपयोग करने का आह्वान करते हैं। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी देश की आंतरिक सुरक्षा में लगे प्रत्येक व्यक्ति की सराहना करते हैं। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का प्रयास है कि वर्तमान चुनौतियों, उसके समाधान को लेकर संबंधित व्यक्तियों को जागरूक किया जाए। जागरूकता से समाधान का मार्ग प्रशस्त होता है। इसके दायित्व निर्वहन में जो जिम्मेदारी पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को सौंपी गयी है, उसका यह पहला सोपान है।

हमने एक प्रयास किया है। यह कितना सटीक है, आगे किस तरह के सुधार की गुंजाइश है, यह आप सुझाएंगे, तो हमारा उत्साहवर्धन होगा। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो अपने सामाजिक दायित्व के प्रति सजग है और Digital India में अपनी प्रतिबद्धता दर्शाता है। Carbon Foot Print घटाने के लिए भविष्य के संस्करण Soft copy में भेजी जाएगी। इसके लिए आपसे अनुरोध है कि अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ अपना **Email** एड्रेस हमें भेजें, ताकि भविष्य में आप इस पत्रिका की डिजिटल कॉपी प्राप्त कर सकें।

अपनी जानकारी आप निम्नलिखित ई-मेल आईडी पर भेज सकते हैं

dg@bprd.nic.in

जय हिंद

The Northeast is witnessing all-round development. Once known for blockades and violence, the region is now known for its development strides.

- Sh. Narendra Modi, *Prime Minister of India*

A historic day for the Northeast!PM @narendramodi led GoI has once again decided to decrease the disturbed areas in Nagaland, Assam and Manipur under the AFSPA. This decision has been taken on account of significant improvement in the security situation in North-East India.

- Sh. Amit Shah, *Union Home Minister & Minister of Cooperation*

माननीय गृहमंत्री जी के मार्गदर्शन में सीआरपीएफ देशसेवा के दायित्वों का निर्वहन करने वाला एक सशक्त बल है जो आतंकवाद, उग्रवाद और वामपंथ उग्रवाद के खिलाफ लगातार सफलता प्राप्त कर देश में शांति व्यवस्था कायम रखने में अहम योगदान दे रहा है।

- श्री नित्यानंद राय
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार

Honouring the unwavering commitment of @official_dgar in protecting India's sovereignty & integrity. Their selfless service in battling insurgency in challenging environments has ensured peace & stability in the region. We are very proud of their contributions

- Sh. Nisith Pramanik, *Minister of State (Ministry of Home Affairs and Ministry of Youth Affairs & Sports)*

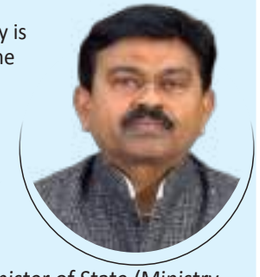

India's cyber security is modernized to meet the challenges of evolving technology. HM Shri @AmitShah ji writes on Safe internet and how Modi govt's cyber security setup will protect India's fast-growing digital economy.

- Sh. Ajay Mishra, *Minister of State (Ministry of Home Affairs)*

Ceasefire Agreements with National Socialist Council of Nagaland/NK, National Socialist Council of Nagaland/ Reformation and National Socialist Council of Nagaland/K-Khango extended

-Ministry of Home Affairs

पुलिस सेवा

नागरिक केंद्रित बनाने का संकल्प

ब्यूरो

30 नवंबर, 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 'स्मार्ट' पुलिसिंग की अवधारणा को देश की जनता के सामने रखा था। उन्होंने कहा था कि एक कारगर खुफिया नेटवर्क वाले देश को सरकार चलाने के लिए किसी हथियार और गोला-बारूद की जरूरत नहीं है। पुलिस बल और खुफिया एजेंसियों पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि वह ऐसा बल चाहते हैं, जो कारगर तरीके से देश की कानून व्यवस्था की देखरेख कर सके।

इस बात के ठीक 8 साल बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी, 2023 को दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 57वें अखिल भारतीय सम्मेलन में पुलिस बल को और संवेदनशील बनाने और उन्हें आधुनिक तकनीकी का प्रशिक्षण देने का सुझाव दिया। साथ ही पुलिस क्षेत्र में हो रहे सुधारों की जानकारी ली। पैदल गश्त जैसी पारंपरिक पुलिसिंग व्यवस्था को और मजबूत बनाने की जरूरत बताई। प्रधानमंत्री की कही गई बात को आत्मसात करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार पुलिस के आधुनिकीकरण प्रक्रिया पर आगे बढ़ते हुए पुलिस बल को स्मार्ट बना रही है।

प्रधानमंत्री ने अप्रचलित आपराधिक कानूनों को निरस्त करने, राज्यों में पुलिस संगठनों के लिए मानकों के निर्माण की अनुशंसा की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने लगातार दौरे कर सीमा के साथ-साथ तटीय सुरक्षा को मजबूत करने पर चर्चा की उन्होंने डेटा प्रवाह को आसान बनाने में नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क के मूल्य पर जोर दिया। जेल प्रशासन में सुधार के लिए जेल सुधारों का प्रस्ताव रखा। बार-बार आधिकारिक यात्राओं के माध्यम से सीमा और समुद्र तट की सुरक्षा बढ़ाने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने उभरती चुनौतियों पर चर्चा करने और अपनी टीमों के बीच सर्वोत्तम तरीकों को विकसित करने के लिए राज्य और जिला स्तरों पर डीजीपी-आईजीपी सम्मेलनों के मॉडल को दोहराने का आह्वान किया। आंतरिक सुरक्षा व कानून व्यवस्था की समस्या से निपटने की रणनीति राज्य और जिला स्तर पर तैयार की जानी चाहिए।

काबिलेगौर है कि अंग्रेजी राज में आंतरिक सुरक्षा तंत्र के गठन और संचालन के पीछे मूल उद्देश्य आम लोगों में भय उत्पन्न करना था। समय के साथ सुधार की बात होने लगी, लेकिन साल 2014 में पहली बार सुधारों की पटकथा लिखनी शुरू हुई। बीते नौ वर्ष में पुलिस पहले से अधिक स्मार्ट और संवेदनशील दिख रही है। बक़ौल प्रधानमंत्री, सबसे अधिक ज़रूरी है पुलिस बलों में प्रोफेशनलिज्म लाना, हर स्तर पर उसमें वर्क कल्चर विकसित करना।

जनवरी, 2023 में हुई पुलिस महानिदेशकों व महानिरीक्षकों की बैठक में प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि जहां हमें बायोमेट्रिक्स आदि जैसे तकनीकी समाधानों का और अधिक लाभ उठाना चाहिए, वहीं पारंपरिक पुलिस प्रणाली जैसे पैदल गश्त आदि को और मजबूत करने की भी आवश्यकता है। उन्होंने अप्रचलित आपराधिक कानूनों को निरस्त करने और राज्यों में पुलिस संगठनों के लिए मानदंड तैयार करने का सुझाव दिया।

बीते नौ वर्ष की अवधि में सरकार की तरफ से पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाये गये। साल दर साल होने वाले पुलिस महानिदेशकों व महानिरीक्षकों के सम्मेलन में स्वयं प्रधानमंत्री ने इस दिशा में कई ठोस सुझाव दिये। प्रधानमंत्री ने क्षमताओं का लाभ उठाने और सर्वोत्तम तौर-तरीकों को साझा करने के लिए राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने उभरती चुनौतियों पर चर्चा करने और अपनी टीमों के बीच सर्वोत्तम तौर-तरीके विकसित करने के लिए, राज्य व जिला स्तरों पर पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन के मॉडल को दोहराने पर भी बल दिया।

वास्तव में बीते नौ साल में देश में हुए पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षकों के सम्मेलनों के मूल मंत्र या थीम का स्रोत

देश की पुलिस का चेहरा बदल रहा है। न सिर्फ अपराधियों की पहचान और उनकी धर-पकड़ में तेजी आई है, बल्कि जांच की गति बढ़ने से अपराध साबित होने की दर भी बढ़ रही है। बीते 7-8 वर्ष में पुलिस सुधार और आधुनिकीकरण की दिशा में सरकार की तरफ़ से उठे क़दमों ने पुलिस बलों को ज़्यादा सक्षम बनाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिशा-निर्देशन और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व ने जनता में पुलिस का भरोसा बढ़ाया है। पुलिस अब पहले से अधिक संवेदनशील और मानवीय हो रही है।

जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस और खुफिया अधिकारियों के व्यापक विचार-विमर्श ही रहे हैं। प्रत्येक थीम के तहत राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सर्वोत्तम तौर-तरीकों (Best Practices) को इन सम्मेलनों के दौरान प्रस्तुत किया जाता रहा है। इसके पीछे सरकार की मंशा यही रही है कि सभी राज्यों को एक दूसरे के अनुभव से सीखने का अवसर मिले।

इसी सीखने और एक-दूसरे को समझने की प्रक्रिया को पहले से अधिक सुलभ बनाने के लिए वर्ष 2014 से ही प्रधानमंत्री पुलिस महानिदेशकों व महानिरीक्षकों के सम्मेलन में गहरी दिलचस्पी लेते रहे हैं। जहां एक ओर पहले इस सम्मेलन में प्रधानमंत्रियों की महज सांकेतिक उपस्थिति हुआ करती थी, वहीं दूसरी ओर अब प्रधानमंत्री इस सम्मेलन के सभी प्रमुख सत्रों में उपस्थित रहते हैं। प्रधानमंत्री न केवल सभी जानकारियों एवं सुझावों को धैर्यपूर्वक सुनते हैं, बल्कि स्वतंत्र और अनौपचारिक चर्चाओं को प्रोत्साहित भी करते हैं, ताकि नए-नए विचार सामने आ सकें।

देश भर में हुए पुलिस महानिदेशकों व महानिरीक्षकों सम्मेलन

- 2014: गुवाहाटी, असम
- 2015: धोरडो, कच्छ, गुजरात
- 2016: राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, तेलंगाना
- 2017: बीएसएफ अकादमी, टेकनपुर
- 2018: केवड़िया, गुजरात
- 2019: आईआईएसईआर पुणे, महाराष्ट्र
- 2020 : वर्चुअली, आईबी मुख्यालय, नई दिल्ली
- 2021: पुलिस मुख्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
- 2022: राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर, पूसा, नई दिल्ली

इससे देश के शीर्ष पुलिस अधिकारियों को, पूरे देश को प्रभावित करने वाली पुलिस व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर, प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर जानकारी देने और उनके समक्ष अपनी निष्पक्ष एवं स्पष्ट सुझाव पेश करने के लिए अत्यंत सौहार्दपूर्ण माहौल मिलता है।

इसका लाभ यह हुआ है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को ध्यान में रखते हुए इन सम्मेलनों में पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़ी भविष्य की थीमों पर भी चर्चा शुरू हो गई है। इससे न केवल वर्तमान में आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी, बल्कि उभरते मुद्दों और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता भी विकसित होगी।

भारत के प्रत्येक सुरक्षा तंत्र को अभेद्य बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जोर सदैव विभागों में बेहतर समन्वय पर रहा है। उनके निर्देशन में केंद्र सरकार हर चुनौतियों के समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई कर रही

है। स्वयं प्रधानमंत्री का कहना है कि हम 5-जी के युग में प्रवेश कर चुके हैं। 5जी से फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकोग्नाइज्ड टेक्नोलॉजी, ड्रोन और सीसीटीवी जैसी टेक्नोलॉजी और उनके प्रदर्शन में कई गुना सुधार होने वाला है। अपराध अब वैश्विक हो गए हैं। घरेलू स्तर के साथ अपराधी अंतरराज्यीय स्तर पर भी सक्रिय हैं। इतना ही नहीं, अपराधियों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। इन परिस्थितियों में अपराध को रोकने के लिए पुलिस बल के लिए आवश्यक है कि वो अपराधियों से 10 कदम आगे रहे।

पुलिस बल पहले से अधिक 'स्मार्ट' होगा, तो नवीन चेतना का संचार होगा। इसका असर हर स्तर की कार्य प्रणाली में दिखेगा। यही सकारात्मकता धीरे-धीरे उपलब्धि बन जाएगी। नतीजतन पुलिस की छवि जनता की नज़रों में सुधरेगी। प्रधानमंत्री ने साल 2014 में हुए सम्मेलन में कहा था कि सोच और समझने की शक्ति व्यापक हो, तो मनोबल बढ़ता है, जिसका असर काम पर सकरात्मक रूप से दिखता है। यह बात हर क्षेत्र में लागू होती है। भारतीय पुलिस के स्वर्णिम भविष्य के लिए प्रधानमंत्री ने नया दर्शन दिया और इसे स्मार्ट पुलिसिंग का नाम दिया। स्मार्ट शब्द की विवेचना करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि पुलिस सख्त और संवेदनशील हो (Strict and Sensitive)। आधुनिक

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को ध्यान में रखते हुए इन सम्मेलनों में पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़ी भविष्य की थीमों पर भी चर्चा शुरू हो गई है। इससे न केवल वर्तमान में आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी, बल्कि उभरते मुद्दों और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता भी विकसित होगी।

और मोबाइल (Modern and Mobile) हो, जिसमें कोई ठहराव न हो। सतर्क और जवाबदेह (Alert and Accountable) हो, विश्वसनीय, उत्तरदायी (Reliable and Responsive) और टेक्नोलॉजी (Tech-savvy and well trained) से युक्त हो। इस स्मार्ट शब्द को पुलिस बल कार्य में शामिल करती है, तो पुलिस बल में नव चेतना का संचार होगा।

कानून-व्यवस्था के पूरे तंत्र के लिए भरोसेमंद होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आम जन से पुलिस का संबंध और संवाद बेहतर होना चाहिए, ताकि उनके बारे में अच्छी धारणा बने। पिछले वर्षों में भारत सरकार के स्तर पर कानून व्यवस्था से जुड़े सुधार हुए हैं, जिसने पूरे देश में शांति का वातावरण बनाने का काम किया है। स्वयं प्रधानमंत्री कहते हैं कि पुलिस के बारे में अच्छी धारणा बनाए रखना 'बहुत महत्वपूर्ण' है और इस राह में जो खामियां मौजूद हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि यद्यपि संविधान के हिसाब से कानून-व्यवस्था राज्यों का विषय है, लेकिन यह देश की एकता और अखंडता से भी उतना ही जुड़ा हुआ है। आंतरिक सुरक्षा के लिए राज्यों का साथ मिलकर काम करना संवैधानिक अनिवार्यता है और साथ ही देश के प्रति जिम्मेदारी भी है।

पुलिस महानिदेशकों व महानिरीक्षकों के सम्मेलनों में प्रधानमंत्री कई बार पुलिस की छवि, जनता से संवाद, लोगों का भरोसा, काम में पारदर्शिता आदि की बात करते हैं। उनका कहना है कि हिंदी फिल्मों में पुलिस बलों का नकारात्मक चित्रण किया जाता रहा है। इसके चलते उनके प्रति जनता में ग़लत धारणा बनी है। इसे सुधारने से पुलिस की छवि जनता की नज़रों में साफ हो सकती है। इसके लिए फिल्मों में पुलिस के समर्पण और बलिदान को दिखाया जाना चाहिए। इसके लिए फिल्म बिरादरी से

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

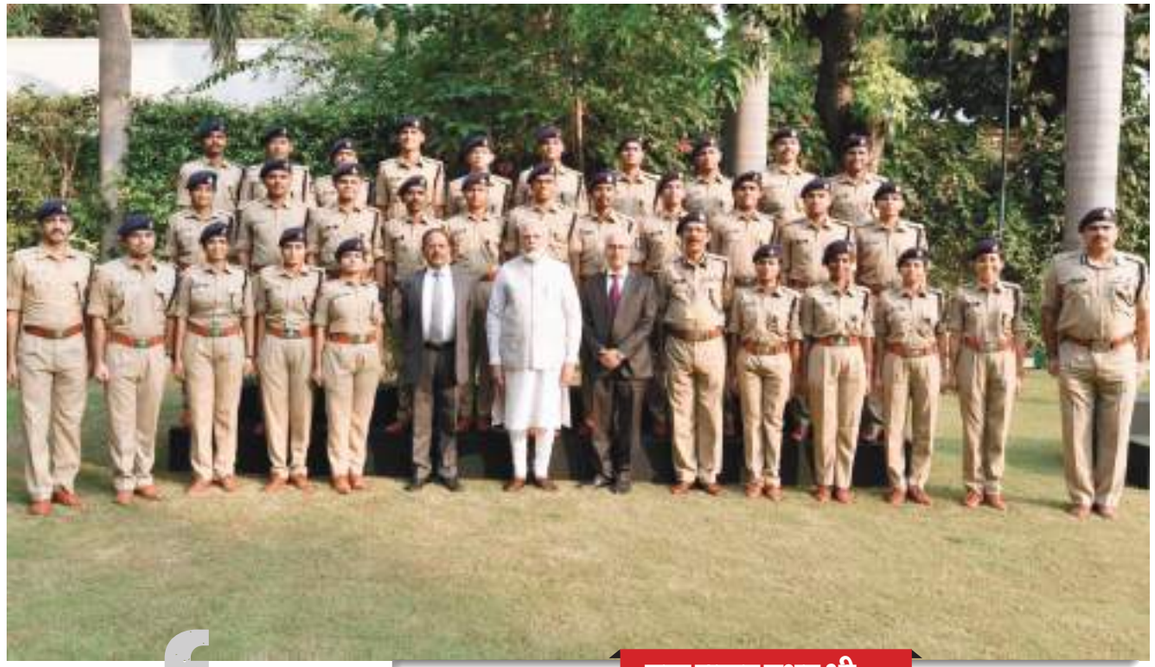

वर्ष 2014 में पुलिस महानिदेशकों व महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन को पहली बार नई दिल्ली से बाहर गुवाहाटी में कराकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक नई परंपरा शुरू की। अलग-अलग स्थानों पर बीते नौ वर्ष में हुए इस सम्मेलन से नया संदेश मिल रहा है।

बातचीत करके पुलिस की छवि पर्दे पर सुधारी जा सकती है। गुजरात के मुख्यमंत्रित्व काल का अनुभव साझा करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि जब वे गुजरात में थे, तो उन्होंने एक छोटा-सा प्रयोग किया था। गुजरात के हर थाने की अलग वेबसाइट थी। इन वेबसाइटों ने जरूरतमंदों की मदद, अपराध की रोकथाम आदि सहित उनके द्वारा किए गए मानवीय कार्यों के संबंध में हर हफ्ते अपनी उपलब्धियों को अपडेट किया। उनके अनुसार, अच्छे काम को प्रचारित करने और पुलिस में समाज का विश्वास स्थापित करने का यह सबसे अच्छा तरीका था। ■

एक नजर इधर भी...

- आजादी के पहले पुलिस के काम में सेवा का नाम नहीं होता था, लेकिन अब सेवा भी है।
- कोरोना जैसी महामारी के दौरान देश भर की पुलिस के योगदान की खूब तारीफ हुई।
- मोबाइल कैमरे द्वारा पासपोर्ट सेवा का सत्यापन होगा और पांच दिनों के अंदर ही अपने घर में आपको सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- मोबाइल फॉरेंसिक साइंस वैन को दिल्ली पुलिस को उपलब्ध कराने से क्राइम के मामलों को जल्द से जल्द सुलझाने और सबूतों को एकत्र करने में मदद मिलेगी।
- आने वाले दिनों में फॉरेंसिक और एविडेंस एक्ट में काफी बदलाव होने वाला है। इसमें 6 साल या उससे अधिक सजा के प्रावधान वाले मामले में ये फॉरेंसिक साइंस वैन का कार्य बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है।
- जी20 कार्यक्रम के दौरान पुलिस को बेहद सतर्क रहना होगा, क्योंकि उस समय कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में होंगे।
- देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था से लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से आतंकियों/पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई हुई, ये किसी से छुपा नहीं है।
- वामपंथी उग्रवादियों के खिलाफ पिछले कुछ सालों के दौरान काफी कार्रवाई हुई है।
- पूर्वोत्तर के राज्यों में भी वहां के स्थानीय लोगों के लिए काफी काम किया है। AFSPA जैसे कानून पर हमने काम किया, इसके साथ ही वहां के कई उग्रवादी संगठनों के प्रमुख नेताओं से बातचीत करके उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा।
- गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की कार्रवाई को दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस का साथ मिला।
- नशा मुक्ति के खिलाफ कार्रवाई हुई। नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करवाते हुए उन्हें सजा दिलवायी गई।

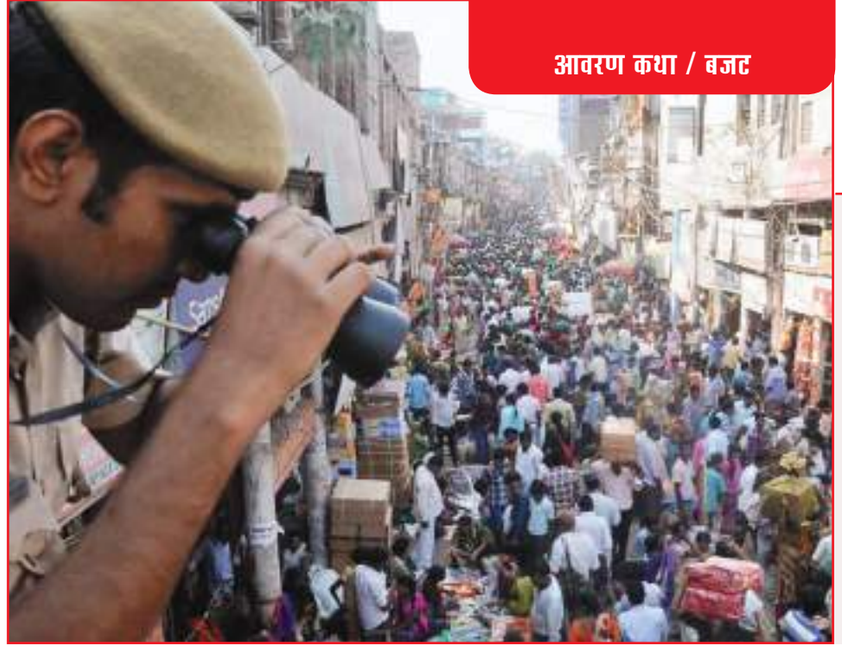

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 'पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की 'अम्ब्रेला योजना' को जारी रखने की मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में 37 सौ करोड़ से अधिक की धनराशि पुलिस सुदृढ़ीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और पुलिस सुधारों के लिए दी गई है।

पुलिस आधुनिकीकरण के लिए बजट में भी की गई व्यवस्था

भारत में पुलिस तंत्र और आपराधिक न्याय व्यवस्था का सिस्टम औपनिवेशिक राज में बनाया गया था। तब पुलिस का प्रमुख उद्देश्य न तो अपराध रोकना था और न ही कानून व्यवस्था पर बहुत ध्यान देना था। पुलिस का प्रथम उद्देश्य था ब्रिटिश राज की जड़ जमी रहे और राजस्व जो अधिकतर भू-राजस्व से आता था, प्राप्त होता रहे। इसलिए पुलिस को कलेक्टर के अधीन रखा गया था। बाद में जब जन जागरूकता बढ़ी और अंग्रेजी राज के खिलाफ लोग मुखर होने लगे तब जाकर आंदोलनों को दबाना और सरकार का इकबाल बनाये रखना प्रमुख कार्य हो गया। यह सोच एक तरह से जनता के मन में बैठ गई। कागजों में और सरकारी फाइलों में समय-समय पर पुलिस सुधार की बात हुई। 2014 के बाद यह उम्मीद बनी कि श्री नरेंद्र मोदी की सरकार पुलिस सुधारों को लागू करने की दिशा में कुछ ठोस काम करेगी।

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 26,275 करोड़ रुपये के खर्च से साल 2021-22 से 2025-26 के लिए 'पुलिस बलों के आधुनिकीकरण' की व्यापक योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की 'अम्ब्रेला योजना' (umbrella scheme) को जारी रखने की मंजूरी दी। यह मंजूरी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों को आधुनिक बनाने एवं उनके कामकाज में सुधार लाने की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहल को आगे ले जाएगी।

राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना में 4,846 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का प्रावधान है। इस योजना के तहत केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर, उग्रवाद प्रभावित उत्तर पूर्वी राज्यों और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए 18,839 करोड़ रुपये के केंद्रीय बजट का प्रावधान भी शामिल है।

भारतीय रिजर्व बटालियनों/विशेष भारतीय रिजर्व बटालियनों की स्थापना के लिए 350 करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय को मंजूरी दी गई है। 50 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ नारकोटिक्स नियंत्रण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना को जारी रखा गया है।

हम पुलिस सुधार के लिए जब उत्तर प्रदेश की ओर देखते हैं, तो पता चलता है कि वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में 37 सौ करोड़ से अधिक की धनराशि पुलिस सुदृढ़ीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और पुलिस सुधारों के लिए दी गई है। बजट में विशेष सुरक्षा बल, पुलिस इमरजेंसी प्रबंध प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और सिटी योजना के तहत महिलाओं की सुरक्षा पर फोकस किया है।

पिछले पांच साल में पुलिस के बजट में करीब दुगुने और पुलिस के आवासीय, गैर-आवासीय भवनों के बजट में चार गुना वृद्धि हुई है। सरकार ने पुलिस महकमे में सबसे ज्यादा धनराशि आवासीय भवनों के लिए 800 करोड़ और गैर-आवासीय भवनों के लिए 800 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। नवसृजित जिलों में पुलिस के आवासीय और अनावासीय भवनों के लिए 300 करोड़ और पुलिस लाइन निर्माण के लिए भूमि खरीद को 65 करोड़ 70 लाख रुपये की धनराशि प्रस्तावित की गई है। ■

टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ता सरोकार

ब्यूरो

"काम अच्छा हो तो सबको दिखता है। कई बार काम अच्छा होता है और आम लोगों तक उसकी सूचना नहीं होती है। ऐसे में आधुनिक संचार माध्यम का सहारा लेकर अच्छे कामों की प्रशंसा करनी चाहिए। नए अनुसंधान और तकनीक को लेकर जनता के बीच जाना चाहिए। पुलिस बलों को भी इसी सोच के साथ काम करना चाहिए। जब आपको शाबाशी मिलेगी और प्रोत्साहित किया जाएगा तो काम में गुणात्मक असर दिखता है।" प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस सोच को देश के पुलिस बलों ने अपनी कार्यशैली में उतारना शुरू कर दिया है। लखनऊ में नवंबर 2021 को आयोजित पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 56वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारतीय पुलिस की खुल कर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आम जनता को 90 फीसदी से अधिक मामलों के बारे में पता नहीं होता। कारण पुलिस और अन्य सुरक्षा बल आपराधिक मामलों के निपटारे की कार्रवाई को जनता के सामने प्रस्तुत ही नहीं कर पाते। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी 25 घटनाओं की पहचान करके उन्हें विभिन्न स्तर के अधिकारियों को सौंप कर यह पता लगाना चाहिए कि लोगों तक इसकी जानकारी क्यों नहीं पहुंच पायी। दरअसल ऐसा करने का मक़सद पुलिस की आंतरिक क्षमता के निर्माण और भविष्य में समस्याओं का निपटारा करने की क्षमता विकसित करना है।

सम्मेलन से पूर्व कारागार सुधार, आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, साइबर अपराध, नारकोटिक्स ट्रैफ़िकिंग, NGOs की विदेशी फंडिंग, ड्रोन संबंधी मुद्दे, सीमावर्ती गांवों का विकास इत्यादि जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों के मुख्य पहलुओं पर चर्चा के लिए पुलिस महानिदेशकों के अनेक कोर ग्रुप गठित किए गए थे। प्रधानमंत्री ने इन सभी चर्चाओं में हिस्सा लिया और अपने सुझाव दिये। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने अपने समापन संबोधन में सभी पुलिस संबंधित घटनाओं के विश्लेषण तथा सीखने की इस प्रक्रिया को संस्थागत करने पर बल दिया। सम्मेलन को हाइब्रिड प्रारूप में करवाने की भरपूर प्रशंसा की और कहा कि इससे विभिन्न स्तर के अधिकारियों के बीच सूचनाओं का प्रवाह सुगम हुआ है। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में एक हाई पावर पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन गठित करने के लिए कहा, ताकि भविष्य की तकनीकों को जमीनी स्तर की पुलिस आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जा सके।

कोविड महामारी के बाद पुलिस के व्यवहार में जनता के प्रति आए सकारात्मक बदलाव की प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में लागू किए गए स्मार्ट पुलिसिंग की नियमित समीक्षा के लिए कहा और उसमें लगातार बदलाव लाने और उसे संस्थागत करने पर बल दिया। साथ ही पुलिस की रोज़मर्रा की समस्या के समाधान के लिए तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को जोड़ने के लिए कहा, ताकि हैकथॉन के माध्यम से तकनीकी समाधान तलाशे जा सके। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि राज्यों की पुलिस को वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के लिए आधुनिकीकरण और टेक्नोलॉजी को आत्मसात करने पर ज़ोर देना होगा।

अप्रैल, 2022 में भोपाल में सीएपीटी में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉफ्रेंस में केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री ने देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आधुनिकीकरण के साथ ट्रेनिंग को आवश्यक बताया। उन्होंने सीसीटीएनएस के माध्यम से पुलिस को लगातार अध्ययन करने की जरूरत भी बताई। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन का गठन कर दिया गया है। इसमें एक्सचेंज ऑफ इनफॉर्मेशन जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। देशभर की राज्य पुलिस को एक जैसे सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे न केवल खर्च कम होंगा, बल्कि उसके परिणाम भी एक जैसे आएंगे। पुलिस टेक्नालॉजी मिशन से देश को फायदा होगा। ■

जी20 बैठक: आतंकवाद का खात्मा करने को प्रतिबद्ध भारत

अर्चना रामसुंदरम
सदस्य, लोकपाल

जी20 समूह का मौजूदा अध्यक्ष होने के नाते इस वर्ष भारत जी-20 देशों के समूह की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करेगा। इसलिए यह स्वाभाविक है कि चर्चा में वे मुद्दे भी शामिल होंगे जो भारत की शांति और सुरक्षा के प्रभावित करते हैं। वैसे भी जी-20 समूह में शामिल होने के बाद से भारत निरंतर आतंकवाद, टेरर फंडिंग जैसे सभी मुद्दों को उठाता रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी20 की लगभग सभी बैठकों में आतंकवाद, टेरर फंडिंग और इसके अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को जड़ से मिटाने जैसे विषय निरंतर उठाते रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ही वर्ष 2022 में भारत में नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित कर भारत की चिंता से अवगत कराया। कॉन्फ्रेंस में श्री शाह ने देश की पुलिस के साथ साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियों के काम के बारे में भी विस्तार से चर्चा की थी। इसके बाद ही केंद्रीय गृहमंत्री की पहल पर नो मनी फॉर टेरर के अंतरराष्ट्रीय सचिवालय की भारत में स्थापना का प्रस्ताव पारित हुआ है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि ये विषय जी20 के अंतिम घोषणापत्रों में स्थान पाने में सफल भी रहे हैं। हाल के वर्षों में, आतंकवाद वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बना है, और भारत सहित कई देशों को अनेक आतंकवादी हमलों का सामना करना पड़ा है। लेकिन प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में जी20 में भारत की सक्रिय भागीदारी ने आतंकविरोधी और अन्य बहुत से मुद्दों पर दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने में मदद की है।

भारत की अध्यक्षता में G20 का नारा 'वसुधैव कुटुंबकम' या 'एक पृथ्वी-एक कुटुंब-एक भविष्य' है। 'वसुधैव कुटुंबकम्' के माध्यम से भारत विश्व को आश्वस्त करना चाहता है कि वह केवल अपना ही नहीं, बल्कि समस्त विश्व के कल्याण की कामना करता है और उसके लिए प्रयासरत रहता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हाल में बने भू-राजनीतिक हालात ने पूरी दुनिया के विकास के लिए जोखिम पैदा किया है। रूस-यूक्रेन युद्ध के साये में यूरोप से लेकर एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। पूरी दुनिया में आपूर्ति की व्यवस्था बाधित हुई है जिसका असर आर्थिक विकास पर दिख रहा है।

भारत समेत दुनिया के कई देश आतंकवाद से प्रभावित हैं। टेरर फंडिंग पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन कर उभरा है। यही वजह है कि भारत आतंकवादी संगठनों के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने की आवश्यकता को लेकर मुखर रहा है, और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के वैश्विक प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है। इस संदर्भ में, भारत खुफिया जानकारी साझा करने, आतंकवादी समूहों की संपत्तियों को जब्त करने और आतंक के वित्तपोषण पर नकेल कसने के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए वैश्विक देशों के बीच सक्रिय सहयोग की मांग करता रहा है।

भारत जी20 की अध्यक्षता को बहुत गंभीरता से ले रहा है। ऐसे समय में, जब संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था महत्वपूर्ण मुद्दों पर मात्र मूकदर्शक बनकर रह गई हो तो जी20 जैसे संगठन की भूमिका और अहम हो गई है। भारत ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है। इसीलिए भारत मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए मानक तय करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) में एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है। भारत 2010 से FATF का सदस्य रहा है और इसकी बैठकों और पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है। 2019 में, भारत ने FATF की अध्यक्षता संभाली और आतंक के वित्तपोषण से निपटने के अपने प्रयासों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। भारत ने राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चे का आह्वान किया है और वैश्विक देशों से आतंकवादी संगठनों को समर्थन देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

भारत ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपनी तरफ से कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। इनमें विशेष एजेंसियों जैसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) की स्थापना शामिल है। ये एजेंसियां आतंकवादी नेटवर्क पर नकेल कसने और उनके फंडिंग स्रोतों को बाधित करने में सहायक रही हैं। भारत ग्लोबल काउंटर-टेररिज्म फोरम (जीसीटीएफ)और ब्रिक्स काउंटर-टेररिज्म वर्किंग ग्रुप सहित क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद विरोधी पहलों में भी सक्रिय रूप से शामिल रहा है। साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने और आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए सूचनाओं के सुरक्षित आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जी20 के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है। G20 आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसमें सदस्य देश आतंकवाद के वित्तपोषण और राज्य-प्रायोजित आतंकवाद से निपटने के अपने प्रयासों में सहयोग और समन्वय कर रहे हैं। निश्चित ही भारत चाहेगा कि उसकी अध्यक्षता में हो रही जी20 की बैठक में इन विषयों पर विस्तृत चर्चा हो ताकि आतंकवाद को नियंत्रित किया जा सके। ■

आतंकवाद जड़ से मिटाने को प्रतिबद्ध सरकार

प्रधानमंत्री ने नेतृत्व, कौशल और सामूहिक प्रशिक्षण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने पुलिस बल के लिए प्रौद्योगिकी और मानव इंटरफेस के महत्व का विशेष तौर पर उल्लेख किया।

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

ब्यूरो

आतंकवाद पर नियंत्रण पाने के लिए भारत सरकार के प्रयासों को हाल ही में वैश्विक स्तर पर सराहा गया है। यूएस ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म की 'कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2021 : इंडिया' में देश से आतंकवाद को मिटाने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज को लेकर सकारात्मक टिप्पणी की गई है। रिपोर्ट कहती है कि भारत सरकार ने आतंकवादी संगठनों के संचालन का पता लगाने, उन्हें बाधित करने और खत्म करने लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। इन प्रयासों के परिणाम मिले हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में, आतंकवाद ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य भारत के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया है। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिद्दीन, आईएसआईएस, अल-कायदा, जमात-उल-मुजाहिद्दीन और जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांग्लादेश, भारत में सक्रिय आतंकवादी समूह हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई के कारण इन आतंकी संगठनों पर धर-पकड़ की कार्रवाई में तेजी आई है।

इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद से संबंधित जानकारी के संवाद की गति बेहद त्वरित है। कई मामलों में भारत ने आतंकवाद की जांच से संबंधित जानकारी के लिए अमेरिका से अनुरोध किया है तो अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रिया तुरंत मिली है। इतना ही नहीं अमेरिका ने जानकारी के आधार पर खतरों को कम करने का प्रयास भी किया है। अमेरिका समेत अन्य देशों के साथ आतंकवाद संबंधी जानकारी साझा करने और बेहतर समन्वय बनाने के लिए भारत ने अक्टूबर 2021 में अमेरिका के साथ काउंटर टेररिज्म ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की 18वीं बैठक की और उसके बाद नवंबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ दूसरे क्वाड काउंटर टेररिज्म टेबलटॉप अभ्यास की मेजबानी की।

आतंकवाद पर नियंत्रण को लेकर प्रधानमंत्री भी पूरी तरह से सक्रिय हैं। आतंकवादी हमलों में शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों को उन्होंने राष्ट्र की सेवा में बलिदान बताया है। 25-27 नवंबर, 2016 को हैदराबाद की सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में संपन्न पुलिस महानिदेशकों व महानिरीक्षकों तथा केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों के 51वें वार्षिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में अब तक 33,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की शहादत राष्ट्र की सेवा में दिया गया एक महान बलिदान है।

वर्ष 2014 के बाद से देश के विभिन्न प्रदेशों में होने वाले पुलिस महानिदेशकों व महानिरीक्षकों के सम्मेलन में आतंकवाद को लेकर गंभीर चर्चा होती रही है। प्रधानमंत्री स्वयं स्वीकार करते हैं कि केंद्र में सरकार के गठन के तुरंत बाद 2014 में असम के गुवाहाटी में आयोजित सम्मेलन के बाद से इस मंच पर विचार-विमर्श की प्रकृति में गुणात्मक अंतर आया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि अब सुरक्षा तंत्र से जुड़े सभी लोग सामने आ रही चुनौतियों का बेहतर समाधान निकालने के लिए अपने कौशल और क्षेत्र के अनुभव का उपयोग करने में सक्षम बन रहे हैं। सभी बिंदुओं पर एक उपयुक्त ढांचे के अंतर्गत हुई चर्चाओं के परिणामों पर नीति निर्माण के स्तर पर उचित ध्यान दिया जाने लगा है। प्रधानमंत्री के मुताबिक सभी संगठनों में उनकी संरचनात्मक प्रासंगिकता बनाए रखने और उन्हें समसामयिक मुद्दों से निपटने में सक्षम बनाने की और अधिक आवश्यकता है।

हैदराबाद के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि आज का दिन आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने और मानवता के लिए खतरनाक इस सोच को पूरी तरह से समाप्त करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का है। आतंकवाद ने मानवतावाद को चुनौती दी है। वह मानवीय शक्तियों को नष्ट करने पर तुला हुआ है और इसलिए सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व की सभी मानवतावादी शक्तियों को एकजुट होकर आतंकवाद को पराजित करना ही होगा।

आतंकवाद को नियंत्रित करने के प्रयासों में टेरर फंडिंग पर रोक लगाने की भूमिका महत्वपूर्ण है। सरकार ने इस दिशा में कई कदम भी उठाये हैं। नवंबर, 2022 में राजधानी दिल्ली में इसको लेकर एक सम्मेलन भी हुआ था। इस दो दिवसीय ग्लोबल मीटिंग में 75 देशों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि जब तक आतंकवाद का सफाया नहीं हो जाता, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। आतंकवाद वैश्विक खतरा है। वह मानते हैं कि यह मानवता, स्वतंत्रता और सभ्यता पर हमला है। आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती। केवल एक समान, एकीकृत और जीरो टॉलरेंस का दृष्टिकोण ही आतंकवाद को हरा सकता है।

टेरर फंडिंग रोकने के सरकार के प्रयासों के नतीजे भी दिखने लगे हैं। जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने में आतंकवादियों को मिल रही टेरर फंडिंग पर काफी हद तक रोक लगी है। प्रदेश में आये दिन पुलिस व सैन्य बलों पर होने वाली पत्थरबाजी की घटनाओं में तेजी से कमी आई है। आतंकवादियों को विदेशों से मिलने वाली फंडिंग की रफ्तार भी धीमी हुई है। इसके नतीजे देश में आतंकवादी घटनाओं और घरेलू स्तर पर होने वाली घटनाओं में कमी के रूप में प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हैं। आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की पहल पर गृह मंत्रालय ने कई अन्य महत्वपूर्ण कदम भी उठाये हैं। इनमें सिमी जैसे संगठनों पर रोक लगाने के निर्णय शामिल हैं। देश में आतंकवादियों के स्लीपर सेल पर निगरानी और त्वरित कार्रवाई ने ऐसी कई संभावित घटनाओं को रोकने में सफलता अर्जित की है जो बड़ी हो सकती थीं। आतंकवाद के प्रसार में जाली मुद्रा और हथियारों की तस्करी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इस तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में प्रधानमंत्री विमुद्रीकरण को महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। सरकार मानती है कि नकली भारतीय मुद्रा के बिना आतंकवाद से लेकर नक्सलवाद तक कुछ जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री इसमें पुलिस की भूमिका काफी अहम मानते हैं।

अतीत में सुझाए गए कार्रवाई योग्य बिंदुओं को लागू करने में मिली सफलता के आकलन पर भी प्रधानमंत्री का जोर है। प्रधानमंत्री के मुताबिक सफलताओं की सीमा का आकलन पुलिस द्वारा की गई पहलों के ठोस परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि सिर्फ सांख्यिकीय मापदंडों पर। आतंकवाद नियंत्रण के लिए प्रधानमंत्री केवल टेक्नोलॉजी पर नहीं, नियमित पुलिस गश्त और कांस्टेबुलरी आधारित खुफिया जानकारी जुटाने पर भी जोर देते हैं। प्रधानमंत्री के समान केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह भी आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हाल ही में श्री शाह ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की 54वीं स्थापना दिवस परेड में कहा कि देश के किसी भी हिस्से में अलगाववाद, आतंकवाद और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों से सख्ती से निपटा जाएगा। आतंकवाद को बिल्कुल न बर्दाश्त करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की नीति सदैव जारी रहेगी। आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने वाले लोगों की संख्या घटती जा रही है और कई लोग हथियार छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं।

आतंकवाद के विरुद्ध होने वाली कार्रवाई पर हमेशा मानवाधिकार संबंधी प्रश्नचिन्ह खड़े किये जाते रहे हैं। परंतु सरकार मानती है कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई मानवाधिकारों के विपरीत नहीं हो सकती। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए आतंकवाद को जड़ से खत्म करना बेहद आवश्यक है। श्री अमित शाह का कहना है कि मोदी सरकार ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और यह भारत से इस खतरे को खत्म करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि एनआईए ने टेरर फंडिंग के मामले दर्ज किए हैं और इन मामलों ने जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने में काफी हद तक मदद की है। पहले टेरर फंडिंग के खिलाफ कोई उचित कार्रवाई नहीं होती थी। 2018 में पहली बार टेरर फंडिंग के खिलाफ मामले दर्ज किए गए और इस वजह से जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए कोई आसान रास्ता नहीं है। इसने रसद और आपूर्ति श्रृंखला और उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है जिन्होंने आतंकवाद की मदद की थी और समाज में सम्मानपूर्वक रह रहे थे। एनआईए ने उनका पर्दाफाश किया। यह एक बड़ी बात है। ■

26 नवंबर, 2008 की बात

शहीद तुकाराम जी

➲ 26 नवंबर 2008 की शाम जब 10 पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई की भीड़ भरे इलाके और होटल ताज पर हमला किया, तो पूरी दुनिया इस हमले को देखकर सन्न रह गई। लेकिन राज्य और केंद्रीय पुलिस बलों के जांबाज जवानों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए इस हमले में आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और मार गिराया। एक को जिंदा पकड़ने में सफलता हासिल की। इस हमले में 164 निर्दोष लोग मारे गए और सैकड़ों अन्य लोग घायल भी हुए। इस घटना के बाद ही पूरे विश्व में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए माहौल बना।

संवेदनशील पुलिसिंग ने कम की जनता और पुलिस के बीच दूरी

पुलिस बल को समय के साथ सामर्थ्यवान बनाने के लिए काम होता रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मानते हैं कि पुलिस बलों के संवदेनशील होने की भी उतनी ही आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने 21 और 22 जनवरी, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 57वें अखिल भारतीय सम्मेलन में संवेदनशीलता पर विशेष ज़ोर देते हुए राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता बताई।

ब्यूरो

समय और आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन हो, तो उसके परिणाम सकारात्मक होते हैं। 21वीं सदी में भारतीय पुलिस बल को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुलिस बलों की पंक्ति में लाया जाए, इसको लेकर सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। सरकार के प्रयासों से देश भर की पुलिस के प्रदर्शन में सुधार अब दिखने लगा है। पुलिसिंग को उच्चतम स्तर पर ले जाने के अपने विज़न को स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में देश के आला पुलिस अधिकारियों के साथ साझा किया।

प्रधानमंत्री का विशेष ज़ोर पुलिस बलों को अधिक संवेदनशील बनाने और उन्हें उभरती टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित करने पर

रहा। उनका मानना है कि पुलिस बलों को जनता का भरोसा जीतना होगा और जनता का मित्र बनकर काम करना होगा। पिछले दिनों हुई कई घटनाओं ने पुलिस के संवेदनशील होने के प्रमाण दिये हैं। इसका असर भी हुआ है और राज्यों में पुलिस और आम जनता के बीच की दूरी और झिझक में कमी दिखने की शुरुआत हो गई है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पूरे देश में कानून व व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए एजेंसियों के बीच डेटा के आदान-प्रदान को सुगम बनाने के लिए नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क के महत्व पर ज़ोर दिया। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि जहां हमें बायोमेट्रिक्स आदि जैसे तकनीकी समाधानों का और अधिक लाभ उठाना चाहिए, वहीं पारंपरिक पुलिस प्रणाली जैसे पैदल गश्त आदि को और मजबूत करने की भी आवश्यकता है। अप्रचलित आपराधिक क़ानूनों को निरस्त करने और राज्यों में पुलिस संगठनों के लिए मापदंड तैयार करने की आवश्यकता

वैसे तो क़ानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, लेकिन यह राष्ट्र की छवि के मुख्य स्तंभों में से एक है। चूंकि भारतीय पुलिस बल अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरीके से काम करते हैं, इसलिए यह क़ानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है।

है। साथ ही उन्होंने जेल प्रबंधन में सुधार के लिए जेल सुधारों पर भी बल दिया। सीमा के साथ-साथ तटीय सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से बार-बार मौके पर जाकर निरीक्षण करने और वहां तैनात पुलिस बल से बातचीत करने की भी आवश्यकता बताई। पुलिस के क्षमता निर्माण को और अधिक उन्नत करने, क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर ढांचों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा डिजिटल पब्लिक गुड्स को सुरक्षित रखने के लिए अलग नज़रिया अपनाने की ज़रूरत है। नार्को-तस्करी, हवाला तथा अर्बन पुलिसिंग जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र एवं राज्यों के बीच और बेहतर समन्वय की आवश्यकता है।

सम्मेलन में राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने पर ज़ोर देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि 21वीं सदी में भारतीय पुलिस बल कैसे विकसित होगा। वैसे तो क़ानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, लेकिन यह राष्ट्र की छवि के मुख्य स्तंभों में से एक है। चूंकि भारतीय पुलिस बल अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरीके से काम करते हैं, इसलिए यह क़ानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, "आंतरिक सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण और आवश्यक है कि पुलिस बल 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के सिद्धांत पर एक दूसरे के साथ तालमेल

बिठाते हुए आगे बढ़ें।"

ग़ौर करने योग्य तथ्य यह भी है कि पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों की वार्षिक बैठक 2013 तक नई दिल्ली में आयोजित होती रही थीं, लेकिन साल 2014 में जब से केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी, उसके बाद इस सम्मेलन को देश की राजधानी से बाहर ले जाने का निर्णय हुआ। साथ ही इस सम्मेलन में गृह मंत्रालय और खुफिया ब्यूरो को भी शामिल किया गया। यह सिलसिला अब तक जारी है। इस वर्ष सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। दरअसल, प्रधानमंत्री ने 2014 से पूरे देश में वार्षिक डीजीपी सम्मेलनों के आयोजन को भी प्रोत्साहित किया है।

वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में पुलिस बल की टेक्नोलॉजी आधारित क्षमता निर्माण और निरंतर उन्नयन को महत्वपूर्ण बताया। चूंकि टेक्नोलॉजी का विकास और चुनौतियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, पीएम ने नियमित प्रक्रियाओं का पालन करने के बजाय इस क्षमता निर्माण के लिए एक 'ऑटो-पायलट' प्रणाली बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच प्रतिस्पर्धा में हमें ख़ुद को और अधिक सक्षम बनाना होगा।

देश के तमाम पुलिस बल केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश पर काम करते हैं। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को बीआईएस और भारत के गुणवत्ता सलाहकार, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) के साथ विशिष्ट चर्चा करके सभी पुलिस स्टेशनों और पुलिस संगठनों के लिए बीआईएस मानकों के बारे में विचार करने का सुझाव दिया। इसके लिए उन्होंने कुछ राज्य पुलिस प्रमुखों और कुछ केंद्रीय पुलिस बलों के प्रमुखों की एक समिति बनाने का विचार रखा, ताकि ऐसी बारीकियों पर काम किया जा सके और समयबद्ध तरीके से निर्णय लिया जा सके।

प्रधानमंत्री ने क्षमताओं का लाभ उठाने और सर्वोत्तम तौर-तरीकों को साझा करने के लिए राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने पर ज़ोर

सम्मेलन में पुलिस प्रणाली और राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया, जिसमें आतंकवाद से मुकाबला, विद्रोह से मुकाबला और साइबर सुरक्षा शामिल हैं।

दिया। उभरती चुनौतियों पर चर्चा करने और अपनी टीमों के बीच सर्वोत्तम तौर-तरीके विकसित करने के लिए राज्य/ज़िला स्तरों पर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन के मॉडल को दोहराने का सुझाव दिया। सम्मेलन में पुलिस प्रणाली और राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया, जिसमें आतंकवाद से मुकाबला, विद्रोह से मुकाबला और साइबर सुरक्षा शामिल हैं। सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, केंद्रीय गृह सचिव, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक और केंद्रीय पुलिस संगठनों/केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रमुख भी उपस्थित थे। विभिन्न स्तरों के लगभग 600 से अधिक अधिकारियों ने सम्मेलन में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से वर्चुअल तौर पर भाग लिया।

सम्मेलन में केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन का उल्लेख करते हुए, वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने और वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने पर बल दिया। जम्मू-कश्मीर, उत्तर-पूर्व एवं वामपंथी उग्रवाद के संदर्भ में सुरक्षा उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए श्री अमित शाह ने अगले 10 वर्षों की चुनौतियों से निपटने का खाका प्रस्तुत किया।

सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने अपने स्वभावानुसार सभी वक्ताओं को धैर्यपूर्वक सुना। प्रधानमंत्री न केवल सभी की बात सुनते हैं बल्कि वह स्वतंत्र और अनौपचारिक चर्चा को भी प्रोत्साहित करते हैं, ताकि नए विचार सामने आ सकें। यह देश के शीर्ष पुलिस अधिकारियों को प्रधानमंत्री को पुलिसिंग और आंतरिक सुरक्षा के प्रमुख मुद्दों पर सीधे जानकारी देने और खुली और स्पष्ट सिफ़ारिशें देने के लिए अनुकूल अवसर प्रदान करता है। ■

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

पुलिस का एक चेहरा ये भी...

जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त थी, तब भारत में अदम्य साहस का परिचय देते हुए तमाम पुलिस बलों ने करोड़ों लोगों की जीवन रक्षा की। मानवता की नई मिसाल पेश की, जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है।

ब्यूरो

साल 2020 कई आपदाओं को लेकर आया था। कोरोना महामारी और दो चक्रवात। इन कठिन परिस्थितियों में देश के पुलिस बलों का प्रदर्शन बेहद मानवीय और संवेदनापूर्ण रहा। देश के नागरिकों की मदद करने और उन्हें सुरक्षित रखने में पुलिस बलों ने बेहतर कौशल और सामंजस्य दिखाया। बड़े पैमाने पर सामुदायिक भागीदारी के कारण पुलिस बलों ने समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान किया और अपेक्षित परिणाम भी हासिल हुए। इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि भविष्य में कठिन परिस्थितियों से निपटने में सामुदायिक भागीदारी ही काम आएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना महामारी के दौरान पुलिसिंग में सामुदायिक भागीदारी की भूमिका का विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित किया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लागू लॉकडाउन के प्रभावी और सुचारू क्रियान्वयन में पुलिस की भूमिका की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे अभूतपूर्व बताया।

5 दिसंबर, 2020 को पुलिस महानिदेशकों व महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कई अन्य देशों की तुलना में भारत में लॉकडाउन का प्रबंधन कहीं बेहतर था। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के दौर में यह स्थापित हुआ कि पुलिस न केवल कानून और व्यवस्था के रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है, बल्कि आम आदमी के लिए ईज ऑफ़ लिविंग सुनिश्चित करने में एक सहायक प्रणाली के रूप में भी काम करती है। कोई नागरिक जब संकट में हो तो पुलिस हरसंभव सहायता करती है। प्रधानमंत्री का भी कहना है कि पुलिस सरकार का

कोरोना महामारी के दौरान पुलिस का मानवीय चेहरा नजर आया। सुरक्षाकर्मियों ने सराहनीय काम किया। वायरस संकट के समय पुलिस ने लोगों को जागरुक करने के लिए गाने गाए, गरीबों को भोजन उपलब्ध कराया और मरीजों को अस्पताल पहुंचाने का काम किया। लोग इस सबके गवाह बने। कोरोना महामारी के दौरान, मानवता ने ख़ाकी वर्दी के जरिए काम किया।

एकमात्र प्रत्यक्ष प्रतीक है, जो हर व्यक्ति के लिए सहज सुलभ है। पूरे सिस्टम में विश्वास बढ़ाने में पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। वर्दीधारी पुलिसकर्मियों के आचरण से ही विश्वास पैदा होता है। पुलिस आत्मनिर्भर भारत के लिए भी एक उत्प्रेरक है। प्रधानमंत्री ने सभी पुलिस बलों से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जनता के मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील होने का

आग्रह किया। किसी भी ताकत को किसी भी भावना से कुछ गलत बोलने का अवसर नहीं देना चाहिए। अभी भी कुछ कमियां मौजूद हैं, जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। भारत को मजबूत करने और विश्व स्तर पर लोकतंत्र की छवि को निखारने के लिए पुलिस को कुछ क़ानूनों को लागू करने में बहुत सावधान और संवेदनशील होना चाहिए। ज़रूरी है कि कार्य-संस्कृति और एसओपी का विकास हो।

साल 2020 के दो चक्रवातों के दौरान किए गए बचाव और राहत कार्यों के लिए NDRF, स्थानीय पुलिस आदि सहित एजेंसियों की प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की। इन एजेंसियों की तत्परता और साहसिक अभियान से काफी लोगों की जान बची थी। प्रधानमंत्री ने पुलिस से संबंधित सभी घटनाओं के विश्लेषण तथा सीखने की प्रक्रिया के लिए संस्थागत व्यवस्था बनाने पर बल दिया। उन्होंने सम्मेलन को हाइब्रिड प्रारूप में करवाने की भरपूर प्रशंसा की और कहा कि इससे विभिन्न स्तर के अधिकारियों के बीच सूचनाओं का प्रवाह सुगम हुआ है। उन्होंने गृह मंत्री के नेतृत्व में एक 'उच्च स्तरीय पुलिस तकनीक मिशन' गठित करने का सुझाव, ताकि भविष्य की तकनीकों को जमीनी स्तर की पुलिस आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जा सके। सामान्य लोगों के जीवन में तकनीक के महत्व को रेखांकित करने के लिए प्रधानमंत्री ने CoWIN, GEM और UPI का उदाहरण दिया।

साल 2020 को त्रासदी का युग मानना, कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों ने बाढ़ का वीभत्स रूप देखा। असम में मई के शुरुआत से ही बाढ़ ने तांडव शुरू कर दिया था। लाखों लोगों के घर-बार, रोजी-रोटी छिन गई। जरूरतमंदों के लिए राहत शिविर लगाए गए। विस्थापितों के लिए शिविर की व्यवस्था की गई। देश में कई ऐसी तस्वीरें सामने आईं, जहां पुलिस बलों की ओर से आम लोगों की मदद की गई।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट में दर्ज आंकड़ों के अनुसार अत्याधिक वर्षा की वजह से मई से जुलाई के बीच, बिजली चमकने और फिर आकाशीय बिजली के गिरने के कारण 315 लोग मरे, जिनमें 90% उत्तर प्रदेश और बिहार के थे। 27 मई को असम के तिनसुकिया जिले में स्थित ऑयल इंडिया की बागजान गैस व तेल के कुएं में भीषण आग लग गई। कुएं से बेतहाशा गैस का रिसाव हो रहा था। जिससे आग और भड़क रही थी। लगातार पांच महीनों तक आग की लपटें उठती रहीं। इस आग ने दो लोगों की जान ली, कई घरों को तबाह किया, और आस-पास के गांवों से लगभग 9000 लोगों को बेघर कर दिया। यहां भी राज्य आपदा बल के साथ स्थानीय पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तत्परता से लोगों तक राहत पहुंचाई गई।

ओडिशा और पश्चिम बंगाल में जब चक्रवात यास आया, तो एनडीआरएफ ने राज्य पुलिस बल के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया। बता दें कि 26 मई, 2021 को चक्रवाती तूफान 'यास' के कारण ओडिशा के जगतसिंहपुर में एक नदी में नौका के पलट जाने के बाद जिला प्रशासन और NDRF ने मिलकर 10 लोगों को बचा लिया था। यास से निपटने के लिए NDRF की ओर से पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 113 टीमों को पहले ही तैनात कर दिया गया था। बचाव अभियान के लिए इस तरह की यह अब तक की सबसे बड़ी तैनाती कही गई। इन टीमों को पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा अंडमान और निकोबार द्वीप में तैनात किया गया था। जब यास आया, तो उससे हुई क्षति से उबरने के लिए NDRF ने बेहतरीन काम किया। जिसकी प्रशंसा प्रभावित राज्यों की सरकारों ने भी की थी। ■

पुलिस परिवारों के लिए है मोदी सरकार

-श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

जब कोरोना संकट आया, तो पूरी दुनिया अचंभित थी। चिकित्सा जगत से जुड़े लोग हों या वैज्ञानिक, किसी को पता नहीं था कि इस महामारी से कैसे लड़ा जाए। देश में लॉकडाउन किया गया। चाहे उसके अमलीकरण की बात हो या प्रवासियों की सहायता करने की बात या फिर लोगों की ज़रूरत को पूरा करना, पुलिस के जवानों ने पहली पंक्ति में रहकर कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी। इस दौरान पुलिस बल के 343 जवानों ने अपनी जान गंवाई। जब भी कोरोना का इतिहास लिखा जाएगा, इन वीर जवानों का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आप देश की सुरक्षा करते रहिए और कानून व व्यवस्था कायम रखिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके और आपके परिवारों की रक्षा के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है।

भरोसे का नाम है सीबीआई

ब्यूरो

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई। यह केवल शब्द या संस्थान का नाम भर नहीं है। यह भरोसा है हर देशवासी का। बड़े शहरों और राजनीतिक गलियारों के साथ ही हर ग्रामीण का। संसद और विधानसभा में भी सदस्य सीबीआई जांच की मांग करते हैं। वहीं, ग्रामीण स्तर पर भी लोग सीबीआई जांच में ही भरोसा दिखाते हैं। सच तो यह है कि सीबीआई एक विश्वास का नाम बन चुका है। इस अटूट भरोसे व विश्वास के पीछे छिपा है सीबीआई का काम के प्रति जुझारूपन, जो उनके सफल कामों में साफ-साफ दिखता है।

देश की प्रीमियम इंवेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में सीबीआई ने 60 वर्ष का सफर पूरा किया है। आज भी जब किसी को लगता है कि कोई केस असाध्य है, तो आवाज उठती है कि मामला सीबीआई को दे देना चाहिए। लोग आंदोलन करते हैं कि केस उनसे ले करके सीबीआई को दे दो। यहां तक कि पंचायत स्तर पर भी कोई मामला आता है, तो लोग कहते हैं- अरे भई, इसको तो सीबीआई के हवाले करना चाहिए। जनता का यह भरोसा जीतना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। इसके पीछे पिछले 60 वर्षों में इस संस्थान के अधिकारियों व कर्मचारियों ने सहयोग दिया है। वे सभी बधाई के पात्र हैं। कहना गलत नहीं होगा कि न्याय और इंसाफ के लिए सीबीआई एक ब्रांड बन चुका है। यह भरोसा और इसके लिए पिछले 60 वर्षों में जिन-जिन ने योगदान दिया है इस संगठन में रहे सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं। ऐसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के हीरक जयंती समारोह के उद्घाटन पर कहा। यह समारोह नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने पोस्टल स्टांप और डायमंड जुबली मार्क वाला सिक्का भी लॉन्च किया। मुख्य रूप से सीबीआई की जिम्मेदारी भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने की है। भ्रष्टाचार, कोई सामान्य अपराध नहीं होता। भ्रष्टाचार, गरीब से उसका हक छीनता है, अनेक अपराधों को जन्म देता है। भ्रष्टाचार, लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। विशेष रूप से जब सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार हावी रहता है, तो वो लोकतंत्र को फलने-फूलने नहीं देता। जहां भ्रष्टाचार होता है, वहां सबसे पहले युवाओं के सपने बलि चढ़ जाते हैं, युवाओं को उचित अवसर नहीं मिलते हैं। वहां सिर्फ एक विशेष इकोसिस्टम ही फलता-फूलता है। भ्रष्टाचार, प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और यहीं से भाई-भतीजावाद, परिवारवाद को बल मिलता है। जब भाई-भतीजावाद और परिवारवाद बढ़ता है, तो समाज का, राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता जाता है। और जब राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता है, तो विकास अवश्य प्रभावित होता है।

यदि बीते 10 वर्ष की राजनीति की बात की जाए, तब कांग्रेस की सरकार थी और सरकार के हर फैसले, हर प्रोजेक्ट, सवालों के घेरे में थे। करप्शन के हर केस में, पहले के केस से, बड़ा होने की होड़ लगी हुई थी, तूने इतना किया तो मैं इतना करके दिखाऊंगा। आज देश में इकॉनॉमी के साइज के लिए लाख करोड़ यानि ट्रिलियन डॉलर की चर्चा होती है। लेकिन तब, घोटालों के साइज के लिए लाख करोड़ की टर्म मशहूर हुई थी। इतने बड़े-बड़े घोटाले हुए, लेकिन आरोपी निश्चिंत थे। उन्हें पता था कि तब का सिस्टम उनके साथ खड़ा है। इसका असर क्या हुआ? देश का व्यवस्था पर से भरोसा टूट रहा था। पूरे देश में करप्शन के खिलाफ आक्रोश लगातार बढ़ रहा था। इससे पूरा तंत्र छिन्न-भिन्न होने लगा, लोग फैसला लेने से बचने लगे, पॉलिसी पैरालिसिस का माहौल बन गया। इसने देश का विकास ठप कर दिया। देश में आने से निवेशक डरने लगे। करप्शन के उस कालखंड ने भारत का बहुत ज्यादा नुकसान किया।

साल 2014 में मोदी सरकार आने पर सरकार का पहला दायित्व, व्यवस्था में भरोसे को फिर कायम करने का रहा। इसलिए सरकार ने काले धन को लेकर, बेनामी संपत्ति को लेकर, मिशन मोड पर एक्शन शुरू किया। आज हम इंटरनेट बैंकिंग की बात करते हैं, UPI से रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। लेकिन हमने 2014 से पहले का फोन बैंकिंग वाला दौर भी देखा है। ये वो दौर था, जब दिल्ली में प्रभावशाली राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के फोन पर हजारों करोड़ रुपए के बैंक लोन मिला करते थे। इसने हमारी अर्थव्यवस्था के आधार, हमारे बैंकिंग सिस्टम को बर्बाद कर दिया था। बीते वर्षों में हम बहुत मेहनत करके अपने बैंकिंग सेक्टर को मुश्किलों से बाहर निकाल करके लाए हैं। ■

अपने स्थापना काल से लेकर आज तक 60 सालों की यात्रा में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने रायसीना हिल्स से लेकर हर गांव तक भरोसा कायम किया है। इस बात को हीरक जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने भी सराहा और सीबीआई के अधिकारियों-कर्मचारियों को बेखौफ होकर कर्तव्य निर्वहन के लिए कहा।

साइबर अपराध पर कसना होगा शिकंजा

ऑनलाइन धोखाधड़ी से लोगों को सतर्क और जागरूक करने के लिए सरकार की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर डिजिटल धोखाधड़ी से जुड़े विज्ञापन, पुलिस से मदद लेने के लिए हेल्पलाइन और कैच-अप जैसे ढेरों उपाय अपनाए गए हैं। लेकिन तेजी से बढ़ते अपराधों पर लगाम नहीं कसी जा सकी है।

ब्यूरो

सुविधा और सहूलियत के साथ ही समस्याएं आती रहती हैं। जब समस्याएं हों, तो उसका समाधान करना होता है। सतर्क रहना होता है। डिजिटल के युग में साइबर अपराध को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। जैसे-जैसे हम रोजमर्रा के कामों में डिजिटली एक्टिव हो रहे हैं, साइबर अपराध की संख्या में वृद्धि हो रही है। भारत में साइबर हमलों की मुख्य वजह धोखाधड़ी को ही माना जाता है। भारत 560 मिलियन से अधिक इंटरनेट यूजर्स के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइल मार्केट है, इस मामले में भारत केवल चीन से पीछे है। ऐसा अनुमान है 2023 तक देश में 650 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट उपयोगकर्ता होंगे। इतना विशाल मार्केट होने के कारण यहां साइबर अपराधों में दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है। भारत के लोग आसानी से किसी भी जालसाज व्यक्ति पर भरोसा कर लेते हैं। जो मोबाइल पर उनके अकाउंट से जुड़ी जरूरी जानकारी जैसे ओटीपी, पासवर्ड आदि प्राप्त कर लेते हैं। साइबर स्पेस राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये एक गंभीर चिंता का विषय भी बनता जा रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 में भारत में साइबर अपराध के 52,974 मामले दर्ज किये गए, जो वर्ष 2020 (50,035 मामले) की तुलना में से 5 प्रतिशत से अधिक और वर्ष 2019 (44,735 मामले) की तुलना में 15 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को दर्शाते हैं।

यद्यपि भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये कई कदम उठाए हैं, जिनमें सभी प्रकार के साइबर अपराध से निपटने के लिये गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (Indian Cyber Crime Coordination Centre- I4C) की स्थापना करना भी शामिल है, लेकिन अवसंरचनागत कमियों को दूर करने के लिये अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

बता दें कि इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से जब किसी व्यक्ति, संगठन पर गुप्त रूप से विभिन्न प्रकार के आपराधिक अथवा गलत कार्य

किये जातें हैं (चोरी, धोखाधड़ी, जालसाजी, मानहानि), जो की उसकी गोपनीयता के साथ उसके निजी जीवन को भी प्रभावित करता है, उसे हम साइबर अपराध कहते हैं। मैलवेयर, वायरस, ट्रोजन, स्पाइवेयर, बैकडोर आदि जो रिमोट एक्सेस की अनुमति देते हैं। 'डिस्ट्रिब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस' (DDoS), जो सर्वर एवं नेटवर्क पर फ्लडिंग (Flooding) की स्थिति उत्पन्न करता और उन्हें अनुपयोगी बना देता है। 'डोमेन नेम्ड सिस्टम पॉइजनिंग अटैक' (DNS Poisoning Attacks) जो DNS को भेद्य बनाता और वेबसाइटों को धोखापूर्ण साइटों की ओर रीडायरेक्ट करता है।

स्वयं प्रधानमंत्री का कहना है कि हम 5-जी के युग में प्रवेश कर चुके हैं। 5जी से फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकोग्नाइज्ड टेक्नोलॉजी, ड्रोन और सीसीटीवी जैसी टेक्नोलॉजी और उनके प्रदर्शन में कई गुना सुधार होने वाला है। मोदी सरकार ने कमान संभालते ही इनफार्मेशन और डाटा सिक्योरिटी क्षेत्र में कोआर्डिनेशन, एक्सचेंज व शेयरिंग को बढ़ावा देने की रणनीति अपनाई थी। इसके तहत साइबर अपराधों की रियल-टाइम रिपोर्टिंग, फोरेंसिक प्रयोगशाला नेटवर्क, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइबर स्पेस की साइबर हाइजीन सुनिश्चित करना और साइबर जागरूकता, जैसे विषयों में काम किया गया है। इसके अतिरिक्त, विदेशी मूल के अपराधियों का राष्ट्रीय डाटाबेस यानी 'एनडीओएफओ' भी तैयार किया गया है।

साइबर अपराध किसी भी बड़ी कंपनी, राजनीतिक पार्टियों और किसी भी आम व्यक्ति के साथ किया जा रहा है। भारत के प्रत्येक सुरक्षा तंत्र को अभेद्य बनाने के लिए प्रधानमंत्री का जोर सदैव विभागों में बेहतर समन्वय पर रहा है। उनके निर्देशन में केंद्र सरकार हर चुनौतियों के समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई कर रही है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक सम्मेलन में साइबर सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए जनता को साइबर अपराधों से मुक्त रखने की आवश्यकता पर बल दिया। साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए क्षमताओं को तेजी से विकसित करना होगा। साइबर सुरक्षा एक बड़ा ख़तरा बना हुआ है। इससे लड़ने के लिए नौजवान और टेक्नोलॉजी में रुचि रखने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मियों का योगदान महत्वपूर्ण है। ज़िला स्तर तक किये जाने वाले प्रयास सकारात्मक नतीजा देने में सक्षम होंगे।

एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि साल 2019 में अपराध दर 3.3 से बढ़कर 2020 में 3.7 हो गयी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में अधिकतर केस धोखाधड़ी के मकसद से दर्ज किए गए। 2020 में 60.2 प्रतिशत मामले तकरीबन (50,035 मामलों में से 30,142) दर्ज किए गए। जबकि 6.6 प्रतिशत (3,293) मामले यौन शोषण के पाए गए। इसके अलावा 4.9 प्रतिशत (2,440) केस जबरन वसूली के जारी किए गए थे।

आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी के 4047 मामले, ओटीपी जालसाजी के 1093 केस, डेबिट क्रेडिट कार्ड से ठगी की 1194 घटनाएं, और एटीएम से सम्बन्धित 2160 मामले दर्ज किए गए। रिपोर्ट में बताया गया कि सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना के 578 केस, ऑनलाइन परेशान करने या महिलाओं और बच्चों को साइबर धमकी से जुड़े 972 मामले, जबकि फर्जी प्रोफाइल के 149 और आंकड़ों की चोरी के 98 मामले दर्ज किए गए हैं।

भारत में साइबर अपराध से निपटने और लोगों को इसके खतरों से जागरूक कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनेक कदम उठाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय में 2017 में साइबर और सूचना सुरक्षा (सीआईएस) प्रभाग बनाया गया था। इसके बाद गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के निर्देशन में 10 जनवरी 2020 को साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)' की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत सात संस्थाएं/प्लेटफॉर्म्स भी लांच किए गए। इनमें नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिकल यूनिट, नेशनल साइबर क्राइम फॉरेंसिक लेबोरेटरी, नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर, ज्वाइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टीगेशन टास्क फोर्स, साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट, नेशनल साइबर क्राइम रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल शामिल हैं।

गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 17 अगस्त 2022 को एनएएफआईएस की शुरुआत की है। इसके तहत अब तक एक करोड़ (1,05,80,266 रिकार्ड्स) से अधिक रिकॉर्ड को इंटीग्रेट किया गया है। 31 जनवरी 2023 तक फिंगरप्रिंट्स को अब तक 23,378 बार चेक किया जा चुका है।

भारत में अपराध में शामिल विदेशियों की रजिस्ट्री, यह सेवा 20 जनवरी 2023 को शुरू की गई है। यह सभी विदेशी अपराधियों के संबंधित डाटा के लिए एक-स्टॉप समाधान है। यह प्रणाली सभी पुलिस स्टेशनों और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के लिए उपलब्ध है। इसका लाभ नागरिक भी उठा सकते हैं। जैसे वैवाहिक विवाद, बीजा धोखाधड़ी, अवैध आप्रवासन, नाइजीरियाई लॉटरी और अन्य साइबर अपराधों, मसलन विदेशियों द्वारा उनके खिलाफ किए गए अपराधों में कमी के माध्यम से नागरिक लाभान्वित होते हैं। ■

'सीसीटीएनएस' का भरपूर इस्तेमाल

क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम यानी 'सीसीटीएनएस' का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। क्राइम रोकने और जांच कार्य में इस सिस्टम से बड़ी मदद मिल रही है। देश के 16,625 पुलिस थानों में सीसीटीएनएस लागू कर दिया गया है। मौजूदा स्थिति में 99.9% पुलिस स्टेशन (16,597) सीधे सीसीटीएनएस पर सौ फीसदी केस दर्ज कर रहे हैं। नागरिकों की ओर से 12.82 करोड़ से अधिक सेवा अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनमें से 12.35 करोड़ अनुरोधों का राज्य पुलिस द्वारा निपटान किया गया है। इसके साथ ही इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) का उपयोग किया जा रहा है। इसके मुख्य स्तंभों को गृह मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र साइलो के रूप में विकसित किया गया था, जैसे कि सीसीटीएनएस के रूप में ई-पुलिस, ई-कोर्ट, ई-जेल, ई-फोरेंसिक और ई-अभियोजन आदि। ई-पुलिस, सीसीटीएनएस के रूप में सौ फीसदी पुलिस स्टेशनों में लागू है। ई-फोरेंसिक एप्लीकेशन को 117 फोरेंसिक लैब में लागू किया गया है। 1300 जेलों में ई-जेल सिस्टम लागू है। ई-अभियोजन आवेदन, 751 अभियोजन जिलों में लागू किया गया है।

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

एक रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे

स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए कई असाधारण काम किए। गुजरात में उनकी प्रतिमा 'स्टेच्यू ऑफ यूनिटी' की छत्रछाया में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस के आला अधिकारियों से संवाद किया, तो उसका सख्त संदेश पूरे देश में गया। आंतरिक सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

ब्यूरो

एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करते हुए आज देश में सामाजिक, आर्थिक और संवैधानिक एकीकरण का महायज्ञ चल रहा है। जल, थल, नभ, अंतरिक्ष हर मोर्चे पर भारत का सामर्थ्य और संकल्प अभूतपूर्व है। अपने हितों की सुरक्षा के लिए भारत आत्मनिर्भरता के नए मिशन पर चल पड़ा है। इस बात को जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, तो इसके पीछे उनकी स्पष्ट सोच और कार्ययोजना प्रतिबिंबित होती है।

केवड़िया के प्रांगण में देश के तमाम पुलिस महानिदेशक व महानिरीक्षकों की जुटान हुई, तो एक नई सोच के साथ कई कार्ययोजनाओं में तेजी लाई गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 दिसंबर, 2018 को दो दिवसीय पुलिस महानिदेशकों व महानिरीक्षकों के इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सम्मेलन में होने वाली चर्चाओं की निरंतरता का क्रम बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि वरिष्ठतम स्तर के अधिकारियों के साथ-साथ चर्चा में राज्यों के एक या दो अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस सम्मेलन का हिस्सा बनें।

ऐसा करने से न सिर्फ केवल सम्मेलन का दायरा बढ़ता है, बल्कि दीर्घकालिक दृष्टि और विचार प्रक्रिया तैयार करने के प्रयास में सहायता भी मिलती है। यह सम्मेलन सूचनाओं के आदान-प्रदान, गेट-टुगेदर, थिंक टैंक, रिपोर्टिंग या लोगों को काम पर लगाने के लिए एक मंच नहीं था, बल्कि यह भारत के भविष्य के लिए एक रोडमैप है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि विभाजनकारी ताकतें अक्सर नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे देश की दीर्घकालिक प्रगति प्रभावित होती है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए एकता को मजबूत करना होगा। साथ ही देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए एकजुट करने वाली ताकतों को मजबूत करना होगा और विभाजनकारियों को अलग-थलग करने के लिए पुलिस बलों को सशक्त बनाना होगा। यह सभी स्तरों पर पुलिस की क्षमताओं को बढ़ाकर ही किया जा सकता है। जैसे-जैसे विभाजनकारी ताकतें अलग-थलग होती जाएंगी और उनके पोषण के स्रोत और भावनाओं का शोषण करने की उनकी क्षमता कम होती जाएगी, वैसे-वैसे कानून और व्यवस्था की घटनाओं की संख्या में भी कमी आएगी।

उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता मिलने के बाद साल 1948 में भारत में पहली बार पुलिस महानिदेशकों का सम्मेलन हुआ था। राजधानी दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन देश के पहले केंद्रीय गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने किया था। साल 2018 में पुलिस महानिदेशकों का सम्मेलन गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित किया गया। सरदार पटेल के आभामंडल से युक्त माहौल में हुए इस सम्मेलन का मूल विषय था - 'सरदार पटेल का राष्ट्रीय एकता का संदेश'। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में साइबर सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए जनता को साइबर अपराधों से मुक्त रखने की आवश्यकता पर बल दिया।

तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद 20 दिसम्बर, 2018 को इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। उल्लेखनीय बात यह भी रही कि 21 दिसंबर, 2018 को सरदार वल्लभभाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में भारतीय पुलिस की ओर से परेड आयोजित की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक, यह परेड महान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि है। सरदार पटेल की दूरदर्शिता के कारण पूरे राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र का विकास हुआ। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इस परेड ने गर्व की भावना पैदा की होगी और डेलिगेट्स को सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृष्टि और योगदान की सराहना करने के लिए प्रेरित किया होगा। प्रधानमंत्री ने भारतीय पुलिस के इतिहास में आयोजित सभी परेडों में से, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर हुई परेड को बेहद महत्वपूर्ण बताया और इसे पूरे देश के पुलिस बल के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटना करार दिया।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दुख होता है, जब जनता पुलिस का सम्मान नहीं करती और समाज को पुलिस पर गर्व नहीं होता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि डेलिगेट्स यह सुनिश्चित करें कि योग्य पुलिसकर्मियों को समाज से उचित मान्यता मिले। दूरदराज के स्थानों और कठोर मौसम सहित पुलिस की कठिन कामकाजी परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे क्षेत्रों में सेवा करना कोई मामूली बात नहीं है। सम्मान कोई चीज़ नहीं है, जिसे कहीं से ख़रीद लिया जाए। पुलिस के लिए सम्मान भी कुछ ऐसा ही है। कोई बाहरी प्रयास पुलिस के लिए सम्मान नहीं लाएगा। पुलिस के बारे में जनता की धारणा को बदलने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना समय की आवश्यकता थी, जो मुख्य रूप से पुलिसकर्मियों के व्यवहार संबंधी मुद्दों के कारण विकसित हुई थी।

समाज और पुलिस के बीच निकटता स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री ने कुछ सुझाव दिये। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन के स्तर पर सालाना दो से तीन कार्यक्रमों के आयोजन हों। पुलिस थाना क्षेत्र के बुजुर्गों और सम्मानित व्यक्तियों की उपस्थिति में पुलिसकर्मियों का सम्मान किया जाए। कांस्टेबल सहित सभी स्तरों पर प्रत्येक अधिकारी अच्छे काम के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसे अधिकारियों की सराहना करने वाले वरिष्ठ अधिकारी न केवल दूसरों को प्रेरित करेंगे, बल्कि उन्हें उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और उनके लिए सार्वजनिक सम्मान बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। यह देखते हुए कि अच्छे जनसंपर्क कौशल वाले अधिकारी ख़ुद को प्रमुखता से पेश करने में सक्षम होते हैं, उन्होंने ऐसे समर्पित मूक कार्यकर्ताओं को सामने लाने की आवश्यकता पर बल दिया, जिनके काम पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। मुख्य रूप से सांप्रदायिक मुद्दों का हल निकालने के लिए विभिन्न समुदाय के सदस्यों के साथ पुलिस स्टेशन स्तर की समन्वय बैठकों के अनुभवों के महत्व को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री ने सकारात्मक लोगों को बढ़ावा देने की रणनीति को शामिल करके अनुभव के दायरे और पहुंच में वृद्धि का सुझाव दिया। यह मानते हुए कि सम्मानित लोगों और अच्छी ताकतों को शत्रुतापूर्ण ताकतों से निपटने के लिए दो तरफा चैनल के माध्यम से प्रोत्साहन की आवश्यकता है। ■

> **आजाद भारत के निर्माण में सबका प्रयास जितना तब प्रासंगिक था, उससे कहीं अधिक आजादी के इस अमृतकाल में होने वाला है। आजादी का ये अमृतकाल, विकास की अभूतपूर्व गति का है, कठिन लक्ष्यों को हासिल करने का है। ये अमृतकाल सरदार साहब के सपनों के भारत के नवनिर्माण का है।**
>
> **- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी**

राष्ट्रीय एकता के लिए नए राष्ट्रीय सम्मान

राष्ट्रीय एकता के लिए देश के पहले केंद्रीय गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान से प्रेरणा ग्रहण करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर राष्ट्रीय एकता के लिए नया राष्ट्रीय सम्मान स्थापित करने की घोषणा की। यह सालाना पुरस्कार प्रत्येक भारतीय के लिए खुला होगा, जिसने किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय एकता के लिए योगदान किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर आधारित एक डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) द्वारा पुलिस के बलिदानों पर आधारित भारतीय पुलिस जर्नल के एक विशेषांक का भी विमोचन किया।

एनडीआरएफ

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

मैत्री का मंत्र और दिया जीवनदान

ऑपरेशन दोस्त मानवता के प्रति भारत के समर्पण और संकट में राष्ट्रों के साथ खड़े होने की हमारी प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है। हमेशा दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी आपदा के लिए भारत सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है।

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

ब्यूरो

तुर्की में आए भीषण भूकंप के बाद जिस तरह से भारत सरकार ने 'ऑपरेशन दोस्त' के तहत तुर्की में सबसे पहले मदद पहुंचाई, उसकी सराहना पूरी दुनिया कर रही है। भारत की ओर से भेजे गए बचाव दल ने भूकंप प्रभावित देशों में कई जानें बचाईं। इस अभियान में एनडीआरएफ की टीम ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अदम्य साहस का परिचय देते हुए कई प्रतिमान स्थापित किए।

वसुधैव कुटुम्बकम् को आत्मसात करते हुए भारत हमेशा ही पूरी दुनिया को एक परिवार मानता रहा है। संकट के समय हर पारिवारिक सदस्य की सहायता करना कर्तव्य माना जाता है। भारत इस साल जी-20 की अध्यक्षता कर रहा है। तुर्की में भीषण भूकंप की सूचना मिलते ही, भोजन, दवा आदि राहत सामग्री लेकर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) का दल तुर्कीवासियों की मदद के लिए निकल पड़ा। हजारों लोगों को नया जीवनदान देने के बाद जब एनडीआरएफ टीम भारत वापसी के लिए विदा हो रही थी, तो तुर्कीवासियों ने टीम के सदस्यों को तालियां बजाकर विदाई दीं।

तुर्की में 30,000 से अधिक लोगों को मलबे से सकुशल बाहर निकालने के बाद एनडीआरएफ के जवान बीती 17 फरवरी को वापस वतन लौटे थे। स्वदेश लौटने पर एनडीआरएफ के जवानों का हिंडन एयरफोर्स हवाई पट्टी पर एनडीआरएफ के आला अधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। एनडीआरएफ जवानों का पहला दल C-17 ग्लोबमास्टर विमान सुबह 9:00 बजे हिंडन एयरपोर्ट पहुंचा था। यहां पर एयरफ़ोर्स के अधिकारियों ने भी एनडीआरएफ को ऑपरेशन दोस्त को सफल बनाने पर बधाई दी थी। 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप के कारण 45,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और दस लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए। इस संकट के समय तुर्की और सीरिया में सबसे पहले मदद पहुंचाने वालों में भारत शामिल था। भारत ने दोनों देशों में पीड़ितों की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया।

जब भारत सरकार की ओर से राहत सामग्री और एनडीआरएफ की टीम को लेकर पहली खेप गई, तो उस उड़ान में 35 टन मानवीय सहायता, राहत सामग्री, चिकित्सा सहायता, आपातकालीन और महत्वपूर्ण देखभाल दवाएं, चिकित्सा उपकरण और उपभोग्य वस्तुएं थीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारतीय टीमें भूकंप प्रभावित तुर्की में राहत और बचाव कार्यों में मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त के तहत दिन-रात काम कर रही हैं।

एनडीआरएफ ने तुर्की में चलाए जा रहे ऑपरेशन दोस्त के दौरान एक 6 साल की बच्ची की जान बचाई। इसको लेकर जैसे ही वीडियो शेयर किया गया, वह वायरल हो गया। इस वीडियो में एनडीआरएफ की टीम के जवानों द्वारा एक बच्ची को मलबे से बचाते हुए दिखाया गया। है। इस बच्ची का नाम बेरेन है। इस वीडियो को भारत सरकार के केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा ''हमें अपने एनडीआरएफ पर गर्व है। तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भारतीय जवानों ने गजियांटेप शहर में एक छह साल की बच्ची बेरेन की जान बचाई। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में हम एनडीआरएफ को दुनिया का सबसे अग्रणी आपदा प्रतिक्रिया बल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।''

'ऑपरेशन दोस्त' की टीम जब स्वदेश लौटी तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन दोस्त से जुड़ी पूरी टीम, एनडीआरएफ हो, सेना हो, वायुसेना हो या हमारी दूसरी सेवाओं के साथी हों, सभी ने बेहतरीन काम किया है। यहां तक कि हमारे बेजुबान दोस्तों डॉग स्क्वायड के सदस्यों ने भी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया है। पहले कुछ दिनों के लिए एनडीआरएफ की टीमों को भूकंप के केंद्र से सिर्फ 23 किमी दूर स्थित गजियांटेप के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया था। बिना पानी, बिजली और सीमित पैक्ड फूड के साथ, बटालियन ने कई लोगों को जिंदा बाहर निकालने के लिए प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों में दिन-रात काम किया।

ऑपरेशन दोस्त के तहत जब तुर्की की मदद की गई, तो एनडीआरएफ टीम को लेकर जाने वाले सी-17 जहाज ने सीरिया के लिए 23 टन और तुर्की के लिए लगभग 12 टन राहत सामग्री का परिवहन किया।

सीरिया के लिए भेजी गई सहायता में स्लीपिंग मैट, जेनरेटर सेट, सोलर लैंप, तिरपाल, कंबल, आपातकालीन और महत्वपूर्ण देखभाल दवाएं, और आपदा राहत उपभोग्य सामग्रियां शामिल थीं। तुर्की के लिए जाने वाली सामग्री में एक सेना क्षेत्र अस्पताल और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की खोज और बचाव दल के लिए आपूर्ति शामिल थी। विमान में ईसीजी मशीन, रोगी मॉनिटर, एनेस्थीसिया मशीन, सिरिंज पंप, ग्लूकोमीटर, कंबल और अन्य राहत सामग्री जैसे चिकित्सा उपकरण थे। ■

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

समय के साथ सोच और सामर्थ्य बढ़ रही है। इससे एक ओर अपराध पर लगाम लग रहा है, दूसरी ओर लोगों की सोच भी बदल रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के साथ केंद्रीय व राज्यों की पुलिस लगातार स्वयं को अपडेट कर रही है।

हर पल अपडेट होती पुलिस

ब्यूरो

समाज में कानून-व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कराने की अहम भूमिका पुलिस बल की है। समय-समय पर इसके आधुनिकीकरण की बात भी होती रही है। सूचना-तकनीक के इस युग में तमाम आधुनिक संचार और तकनीकी सुविधा से पुलिस बलों को लैस होना होगा। स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा है कि अब कानून व्यवस्था किसी एक राज्य के दायरे में सिमटी रहने वाली व्यवस्था नहीं रह गई है। अब अपराध इंटरस्टेट और इंटरनेशनल हो रहे हैं। यानी टेक्नोलॉजी की मदद से एक राज्य में बैठे अपराधी दूसरे राज्य में भयंकर अपराध करने की ताकत रखते हैं। देश की सीमा से बाहर बैठे अपराधी भी टेक्नोलॉजी का जमकर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हर राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल तथा केंद्र और राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल हो यह बहुत जरूरी है।

आगामी 25 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 5 प्रण की बात की है। विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता एवं एकजुटता और सबसे प्रमुख बात नागरिक कर्तव्य। राज्य सरकारों द्वारा अपने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण में सहायता करने की योजना

> **देश भर की पुलिस को ऐसा होना चाहिए कि उसका एक सिस्टम विकसित हो। किसी व्यक्ति के आने या जाने से सिस्टम पर असर नहीं पड़े। कोई भी व्यक्ति पुलिस में रहे, सिस्टम के भीतर ही काम होता रहे। पुलिस टेक्नालॉजी मिशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था जिसे बना लिया गया है। इसमें एक्सचेंज ऑफ इनफॉर्मेशन जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।**
>
> **-श्री अमित शाह**
> केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

के तहत वित्त वर्ष 2018-19 से पुलिस सुधारों के लिए प्रोत्साहन की शुरुआत की गई है। वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्ष की अवधि के दौरान "पुलिस अवसंरचना के उन्नयन के लिए विशेष परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए राज्यों को सहायता" की योजना लागू की गई थी। देश में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों को रैंक और पुरस्कार देने के लिए वार्षिक मूल्यांकन 2017 से आरंभ किया गया है।

वर्ष 2018, 2019, 2020 और 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों से चुनी गई 13 लघु फिल्मों को बीपीआरएंडडी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। डीसीपीडब्ल्यू (समन्वय निदेशालय पुलिस वायरलेस) ने राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस के लिए राष्ट्रीय संचार मानक तैयार किया जिससे उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न संचार उपकरण/ नेटवर्क सुझाए जा सकें। सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए रेडियो संचार उपकरणों के परीक्षण हेतु एसओपी अक्टूबर, 2020 में परिचालित की गई।

डीसीपीडब्ल्यू नई दिल्ली में अपने मुख्यालय और देश भर में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों में फैले 31 आईएसपीडब्ल्यू स्टेशनों के साथ कानून और व्यवस्था, वीवीआईपी/ वीआईपी मूवमेंट आदि से संबंधित संदेशों के आदान-प्रदान के लिए चौबीसों घंटे इंटर स्टेट पुलिस वायरलेस (आईएसपीडब्ल्यू) नेटवर्क कायम रखता है। डीसीपीडब्ल्यू केंद्रीय वितरण प्राधिकरण होने के नाते डीसीपीडब्ल्यू मुख्यालय/नॉर्थ ब्लॉक/सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 31 आईएसपीडब्ल्यू स्टेशनों में कंट्रोल क्रिप्टो सेंटर के माध्यम से वर्गीकृत संदेशों के लिए कवर प्रदान करता है। डीसीपीडब्ल्यू ने अखिल भारतीय डिजिटल सैटेलाइट पुलिस नेटवर्क (पोलनेट1.0) के अपने पिछले सेटअप को पोलनेट2.0 में अपग्रेड किया। डीसीपीडब्ल्यू का इस समय सार्वजनिक सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उनके मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशंस और भविष्य के पीपीडीआर ब्रॉडबैंड नेटवर्क के लिए उपयोग किया जा रहा है। ध्यान देने योग्य यह भी है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित मदों को सुचारू रूप से केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में शामिल करने की विधि दिनांक 15.07.2020 को तैयार की गई है। गृह मंत्रालय और डीआरडीओ के सहयोग से हैंड हेल्ड ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार (एचएच-जीपीआर), व्हीकल माउंटेड ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, 9 एमएम पिस्टल और 40 एमएमयूबीजीआई के लिए कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम, फॉलीज पेनिट्रेटिंग रडार, टनल डिटेक्शन सिस्टम और मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड आदि जैसे विभिन्न सामान विकसित किए जा रहे हैं।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस संगठनों (एसपीओ) के आधुनिकीकरण के लिए 67,451 ए.के. सीरीज आटोमेटिक राइफल्स की फास्ट ट्रैक खरीद की गई है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राज्य पुलिस संगठनों (एसपीओ) और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए बनी इंसास राइफल्स की जगह 39,702 असॉल्ट राइफल्स की खरीद की गई। रक्षा खरीद नीति की तर्ज पर पहली 'केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए व्यापक खरीद नीति' तैयार की जा रही है। विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को हथियार, गोला-बारूद, बुलेट प्रतिरोधी वाहन, जैकेट, हेलमेट, रेडियो उपकरण, दूरबीन, मोनोकुलर, ऑल वेदर फ्लोटिंग बॉर्डर आउट पोस्ट (एफबीओपी) और अन्य वस्तुओं की खरीद के लिए वर्ष 2014 से अब तक 2296.32 करोड़ रुपए के व्यय के लिए स्वीकृति जारी की गई, जिससे राष्ट्रविरोधी तत्वों से निपटने में उनकी क्षमता बढ़ी है और आधुनिकीकृत हुआ है।

बीते दिनों राज्यों के गृह मंत्रियों के दो दिवसीय 'चिंतन शिविर' को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सहकारी संघवाद ना सिर्फ संविधान की भावना है, बल्कि यह केंद्र और राज्यों की जिम्मेदारी भी है। पुलिस के लिए 'एक राष्ट्र, एक वर्दी' सिर्फ एक विचार है। मैं यह आप सभी पर थोपने की कोशिश नहीं कर रहा, इसके बारे में आप सोचिए। यह 5, 50 या सौ सालों में हो सकता है। लेकिन हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए। ■

बीपीआरएंडडी के बगैर अच्छी पुलिसिंग की कल्पना नहीं हो सकती

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के 49वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय पुलिस में बीपीआरएंडडी के योगदान का वर्णन करते हुए केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि पिछले पांच दशकों के दौरान, इस संस्था की यात्रा उल्लेखनीय रही है क्योंकि इसने भारतीय पुलिस को आकार देने में एक अहम भूमिका निभाई है। इसने अपने प्रशिक्षण अंत:क्षेपों तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के जरिये, अनुसंधान एवं राष्ट्रीय मिशन परियोजनाओं के माध्यम से, पुलिस बलों को नवीनतम बदलाव एवं चुनौतियों के साथ गति बनाये रखने के लिए विभिन्न आधुनिकीकरण पहलों के जरिये पुलिस बलों को तैयार किया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, बीपीआरएंडडी ने पुलिस अधिकारियों के क्षमता निर्माण पर फोकस किया है और लगभग 55,000 अधिकारियों तथा लोगों को प्रशिक्षित किया है।

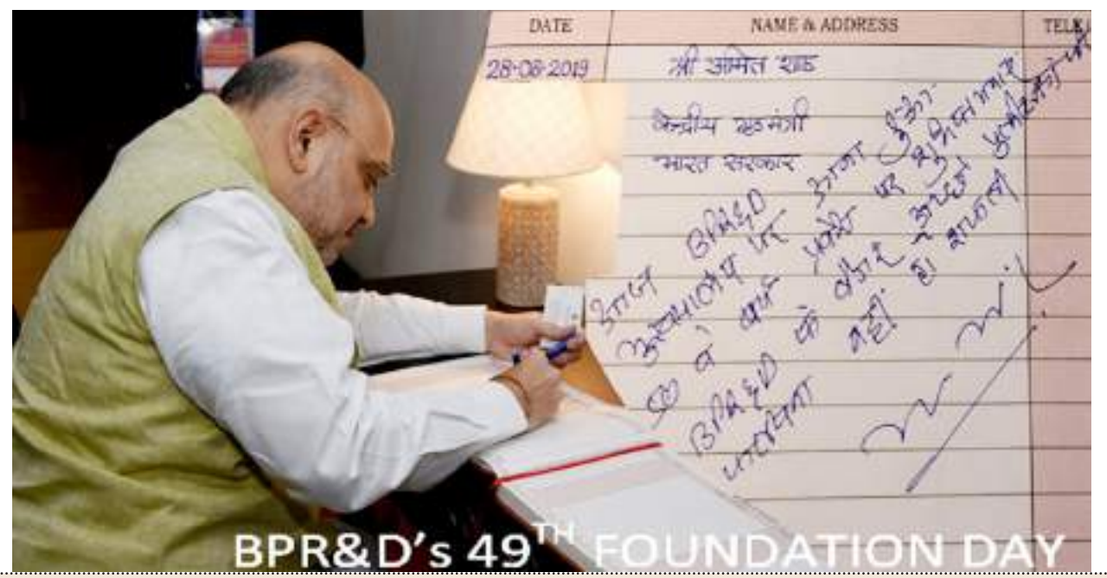

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) के लिए फार्च्यूना पब्लिक रिलेशंस प्रा. लि. नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित व मुद्रित

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग- 48, महिपालपुर,
नई दिल्ली - 110037

BPRDIndia bprdindia officialBPRDIndia Bureau of Police Research & Development India https://bprd.nic.in